www.udayindia.in,editor@udayindia.in FACEBOOK.COM/UDAYINDIAWEEKLY

Published on 29th August 2021, Released on 30th August 2021

पंजाब, उत्तराखंड में कॉंग्रेस की डूबती लुटिया?

भिक्षावृति पर लगे लगाम

रुद्रेश्वर मंदिर वैज्ञानिकी का चमत्कार

उदय इंडिया

वर्ष- 09, अंक-07-08 दिल्ली, सितम्बर 05-11, 2021 मूल्य ₹ 30

भारतीयता का शंखनाद

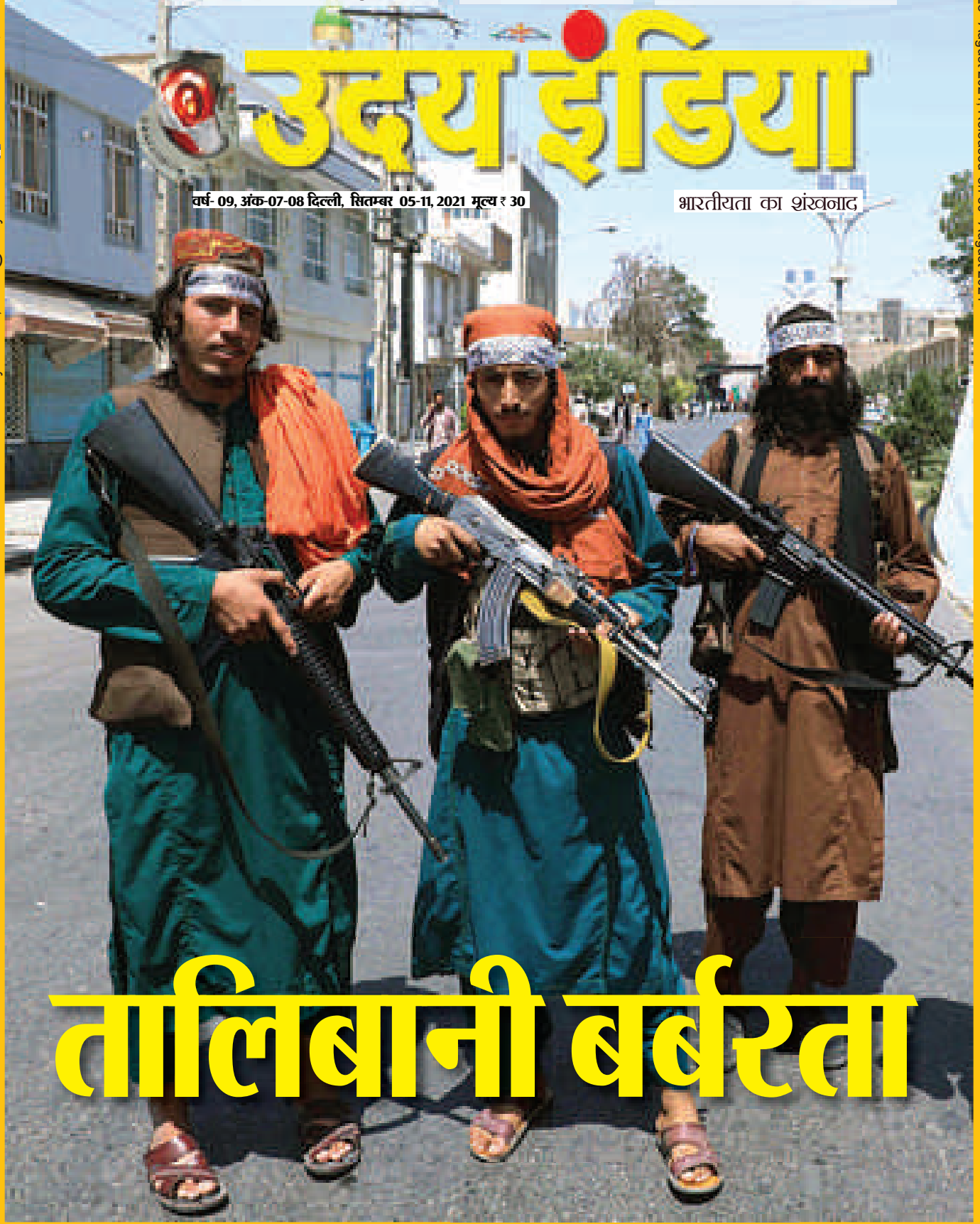

तालिबानी बर्बरता

VISIT…

HCMCT
ManipalHospitals
LIFE'S ON
NEW DELHI

The difference between
a good hospital and a great hospital is
Responsible Healthcare

As a healthcare provider, there is more to Responsibility than treating people and improving their life... something that could take healthcare to the next level of trust.... Responsible Healthcare.

At Manipal, the ethos of care is defined by commitment in small things-Attitudes, Empathy, Response Mechanism, Back-end Systems... The hospital is an entity made up with elements of excellence; human and material alike. Responsible and accountable.
Responsible beyond the protocol.

From the doorman to the super specialist and beyond .... the delivery chain
is linked with the finer values of ethical practices, transparency and patient centricity.
That's Manipal for you.

...you can always trust a Manipal

thebrandwagon.in

Centres of Excellence
Cardiac Sciences | Oncology Sciences | Renal Sciences | Neuro Sciences |
Gastrointestinal & Bariatric Sciences | Orthopaedics | Woman & Child

60 YEARS | a legacy of best PRACTICES

Human Care Medical Charitable Trust

Bengaluru | Salem | Mangaluru | Goa | Vijayawada | Jaipur | New Delhi and Klang(Malaysia)

Sec-6, Dwarka, New Delhi-110075, Website: delhi.manipalhospitals.com 011-4967 4967 011-4040 7070

तालिबान और भारतः आशंका नहीं संकल्प का समय

पिछले चालीस साल में दरअसल हमारी अफगानिस्तान नीति बेहद रक्षात्मक और पराबलम्बी रही है। जब सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो हम उसकी नीति के पिछलग्गू हो लिए थे। सोवियत संघ की गोद में बैठने का ही परिणाम था कि उसके जाने के बाद वहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं था और तालिबान के पिछले शासन में पाकिस्तान ने उसका उपयोग कर हमारे लिए सुरक्षा के गंभीर खतरे खड़े कर दिए।

पेज -12

पेज-08

उ.प्र. के बाद पंजाब, उत्तराखंड में भी डूबेगी कांग्रेस?

राहुल ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी इसी तरह गले की हड्डी बना लिया। उनके ही कारण मध्य प्रदेश की सरकार गयी। राहुल को जरूरत से ज्यादा दिग्गी प्रेम ने मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार मिटवा दी। दिग्गी की सलाह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को कम आंका गया। राज्यसभा की सीट दिग्गी राजा को देना थी तो देते पर सिंधिया को क्यों नहीं दी। दोनों ही लोकसभा का चुनाव हारे थे। सिंधिया के पक्ष में तो 25 से अधिक विधायक थे जबकि दिग्विजय के पास 10, 12 से अधिक नहीं थे। यदि अब दिग्गी का कद कम करते हैं तो मध्यप्रदेश में नुकसान होता है और बनाए रखते हैं तो पार्टी का नुकसान पूरे देश में हो रहा है।

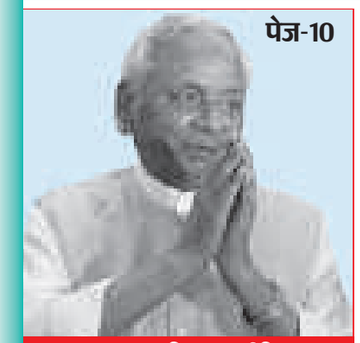
पेज-10

कल्याण सिंहः राजनीति के एक युग का अंत

पेज-44

गीत गाया पत्थरों ने

पेज-46

आप भी बन सकते हैं एक सफल रेडियो जॉकी

अफगानिस्तान में तालिबान के आगमन से उपजा वैश्विक संकट

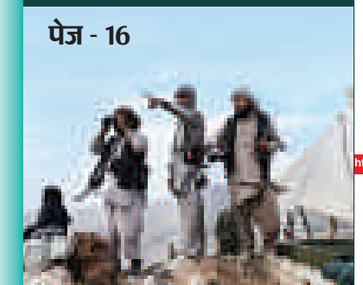
पेज - 16

स्थायी स्तंभ

संपादकीय 07
फिल्म-जगत 48

आवरण पृष्ठ फोटो सौजन्य:
https://twitter.com/mblfrettir/status/1428615416709107715/photo/1

Published on 28th August 2021
Released on 30th August 2021
Total No. of Pages+Covers = 52

देसी गर्ल हिना पेज-48

श्रीराम शरणम् , श्याम शरणम् , श्री हनुमते नमः

उदय इंडिया

www.udayindia.in

संपादकीय निर्देशक- प्रकाश नंदा
संपादक - दीपक कुमार रथ
समाचार संपादक - अशोक कुमार
उपदेष्टा - स्वदेशपाल गुप्ता, एच. आर. नागेन्द्र, सोहन लाल कडेल, नंद किशोर शर्मा, श्रीकृष्ण मुदगिल, भारत भूषण
सलाहकार संपादक - डॉ. विजय खैरा, राहुल कश्यप
ब्यूरो प्रमुख - निर्मल जैन
संवाददाता - महेन्द्र राउत (सूरत), सुदर्शन छोटराय (भुवनेश्वर), दिनेश जिंदल, मनीष शाह (अहमदाबाद), सतीश शर्मा (भुवनेश्वर)
कला निर्देशक - कुन्दन कुमार सिंह
छायाकार - सुभाष कुमार शर्मा

मैनेजर (कॉम्युनिकेशंस एंड पीआर) - संगीता बिष्ट
कार्यालय - बी-84, वेस्ट विनोद नगर, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
फोन नं.- 011-46102483, +918800396718
+918800396719
ईमेल- editor@udayindia.in
बंगलूरू कार्यालय - नं.-11, द्वितीय तल, के.एस.वी. कॉम्पलेक्स, मिलर्स रोड, बंगलूरू-560052, फोन नं.- 080-41472201-02, फैक्स - 08022201704
हैदराबाद कार्यालय - कडेल मार्केटिंग प्रा. लि.,401, मोगल कोर्ट, बशीर बाग, हैदराबाद-500001, फोन नं.-040-23237563, +91-9849033200
अहमदाबाद कार्यालय - एफ - 204, अनुराग अवास, आई.ओ.सी. पैट्रोल पम्प के पास, मेम नगर, अहमदाबाद
जयपुर कार्यालय - 128, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान फोन नं.-09649939888
विज्ञापन के लिए - 011-22479306/07, 8800396719, 8800396718

प्रकाशक, मुद्रक तथा संपादक - दीपक कुमार रथ द्वारा ई-256, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-92 से प्रकाशित एवं एमपी प्रिंटर्स, बी 220, फेज 2, नोएडा, यूपी से मुद्रित; स्वामी - उपाली अपराजिता रथ सर्वाधिकार सुरक्षित, आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

पाठक की ओर से...

सरकार का खेलों को प्रोत्साहन

ओलंपिक के सवा सौ साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत ने सात पदक जीते हैं। ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की थी। अप्रैल 2018 में इसमें कुछ बदलाव किये गए। जो खिलाड़ियों को सहूलियत देने के लिहाज से बेहतर माने जा सकते हैं। इसके तहत कोर ग्रुप में खिलाड़ियों का चुनाव किया गया। इन चुने हुए एथलीटों को पचास हजार रूपए महीने का भत्ता दिया जाना शुरू हुआ। इसी तरह इस योजना के तहत डेवलपमेंट ग्रुप का चुनाव हुआ। इन समूह के खिलाड़ियों को 25 हजार रूपए महीने दिया जाता है। फिलहाल कोर ग्रुप में हाकी खिलाड़ियों के साथ 162 खिलाड़ी और डेवलपमेंट ग्रुप में 254 एथलीटों को चुना गया है। जाहिर है कि इन भत्तों के सहयोग से खिलाड़ियों को बहुत सहूलियत हुई है।

पीताम्बर सेन, *कोलकाता*

भारतीय भाषाओं में हो शिक्षा

भारत एक ज्ञान की सभ्यता और राष्ट्र रहा है। भारतीय ज्ञान की ख्याति संपूर्ण दुनिया में अनादिकाल से रही है। भारत अंग्रेजों के आगमन तक अगर दुनिया का सबसे समृद्ध देश था तो अपनी शिक्षा के कारण ही। जिस दिन से भारत में विदेशी शिक्षा का फंदा पड़ा उसी दिन से भारत की समृद्धि और सौभाग्य घटने लगा और भारत दुनिया के गरीब देशों मे गिना जाने लगा। ज्ञान के साथ भारत में चारित्रिक पूँजी और श्रेष्ठता का भाव भी सदैव विद्यमान रहा। फाह्यान से लेकर अलबरूनी इत्यादि विदेशी यात्रियों नें भारत के नागरिकों के श्रेष्ठता बोध और जीवन की उत्कृष्टता की विपुल चर्चा की है और प्रमाण दिए हैं। अंग्रेजी राज बढ़ने के साथ ही भारतीयों का चारित्रिक पतन भी बढ़ता गया। अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग अपने ही लोगों से कट कर उनके शोषण का यंत्र बन गया। इसलिए भारतीय भाषाओं में भारत की आवश्यकताओं और प्रकृति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था भारतीयों का अधिकार और कर्तव्य दोनों ही है।

अमर सिंह चौहान, *दिल्ली*

अंगदान महादान

कोई भी व्यक्ति चाहे, वह किसी भी उम्र, जाति, धर्म और समुदाय का हों, वह अंगदान कर सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अंगदान के महत्व को समझने के साथ ही अंगदान करने के लिये आम इंसान को प्रोत्साहित करना ही सभी का उद्देश्य होना चाहिए। भारत महर्षि दधीचि जैसे ऋषियों का देश है, जिन्होंने एक कबूतर के प्राणों व असुरों से जन सामान्य की रक्षा के लिये अपना देहदान कर दिया था। परंतु समय के साथ भारत में अंगदान की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई। निश्चित तौर पर अंगदान करके किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा लाया जा सकता है। इस तरह अंगदान करने से एक प्रेरणादायी शक्ति पैदा होती है, जो अद्भुत होती है, यह ईश्वर के प्रति सच्ची प्रार्थना है। इस तरह की उदारता व्यक्ति की महानता का घोतक है, जो न केवल आपको बल्कि दूसरे को भी प्रसन्नता एवं जीवनऊर्जा प्रदान करती है।

अमरीश दुबे, *नागपुर*

PIONEERS IN AEROSPACE
DRIVEN BY TECHNOLOGY
एरोस्पेस के प्रणेता टेक्नोलॉजी के साथ

AERO INDIA
www.hal-india.co.in
HALHQBLR
हिएलि HAL
हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED

Uday India

उदय इंडिया

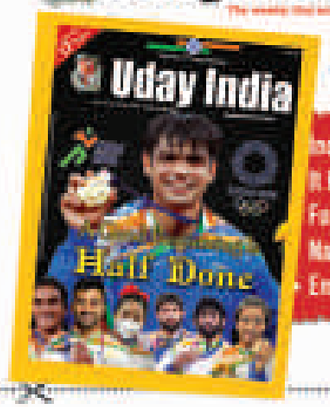

A national weekly with a pioneer spirit

India's Only Nationalistic Weekly With A Large Reach
It Carries Out A Wide Range of Issues Related to Politics, Defence, Foreign Affairs, Economy, Youth Affairs , Education, Agriculture, Cinema, Naturopathy And Many More Issues Of National Importance
Eminent Writers Contribute Insightful Analyses

Yes! I Wish to subscribe to UDAY INDIA For Inquiry: 011-46102482/83, 08800396718/19/23

Please tick your subscription choice and send the form to: E-256, Saraswatikunj Apartment, 25, I.P. Extension, Delhi-110092

Email: subscription@udayindia.in

SUBSCRIPTION FOR UDAY INDIA (ENGLISH)						SUBSCRIPTION FOR UDAY INDIA (HINDI)					
Tick	Year	Cover Price (₹)	Saving	Discount	You Pay (₹)	Tick	Year	Cover Price (₹)	Saving	Discount	You Pay (₹)
☐	5	9100	20%	1820	7280	☐	5	5200	20%	1040	4160
☐	3	5460	10%	546	4914	☐	3	3120	10%	312	2808
☐	1	1820	5%	91	1729	☐	1	1040	5%	52	988

UDAY INDIA COMBO (ENGLISH & HINDI)					
Tick	Year	Cover Price (₹)	Saving	Discount	You Pay (₹)
☐	5	(English) 9100+ (Hindi) 5200=14300	30%	4290	10,010
☐	3	(English) 5460+ (Hindi) 3120=8580	20%	1716	6864
☐	1	(English) 1820+ (Hindi) 1040=2860	10%	286	2574

Please Fill The Form in CAPITAL LETTERS

I am enclosing Cheque/DD No.: _____ dated: _____ drawn at (specify bank) _____

Favouring UDAY INDIA for Rs. _____ (Add Rs.25/- for non Delhi Cheques)

Name: _____ Address: _____

City: _____ State: _____ Pin: _____ Ph (Res): _____

Mobile: _____ Email: _____

OR SUBSCRIBE ONLINE | EMAIL

http://udayindia.in/english/subscription.php | Log in: www.udayindia.in | subscription@udayindia.in

SUBSCRIBE TODAY

Follow us on WWW.UDAYINDIA.IN UDAYINDIAONLINE @UDAYINDIAONLINE

सम्पादकीय ■ दीपक कुमार रथ

दुर्दांत तालिबान

अफगानिस्तान में दो दशकों की सैन्य उपस्थिति के बाद इस क्षेत्र से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के फैसले के बाद अफगानिस्तान के भाग्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गयी हैं। वास्तव में अफगानिस्तान में हुई तालिबानी अमानवीयता, क्रूरता एवं बर्बरता की घटनाओं से जुड़े अनेक प्रश्नों को खड़ा करती है। अफगानिस्तान का लगभग अठारह वर्षों तक अमेरिकी एवं मित्र देशों के साये में जद्दोजहद के बाद फिर अंधेरे सायों एवं अमानवीयता के शिकंजे में चले जाना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक तो है ही, मानवीयता पर कठोर हमला भी है। कथित इस्लामी सत्ता की स्थापना के लिए तालिबान जो कर रहा है, उसकी दुनिया में शायद ही किसी कोने में प्रशंसा होगी। दुनिया स्तब्ध है और भारत जैसे देश तो कुछ ज्यादा ही आहत हैं। बड़ा प्रश्न है कि अठारह वर्षों तक इस मुल्क में तालिबानों से मुकाबला करने के बाद अमेरिकी फौजों ने इस देश का साथ क्यों छोड़ा? प्रश्न यह भी है कि दुनिया में मानवता की रक्षा की वकालत करने वाली महाशक्तियां क्या सोचकर इस अवसर पर चुप्पी साधे रही? भारत सदैव मानवीय मूल्यों का हिमायती एवं रक्षक रहा है। अफगानिस्तान कभी भारत वर्ष का हिस्सा रहा था, इस आधार पर नहीं, पर मानवीयता के आधार पर भारत ने वहां तन-मन-धन से विगत कम से कम बीस वर्षों में भारी निवेश किया। एक उदारवादी एवं मानवतावादी ताकत के रूप में न जाने कितनी विकास परियोजनाओं में भारत की वहां हिस्सेदारी रही। भारत ने वहां अरबों डॉलर के सहायता कार्यक्रम चला रखे हैं, अब उनका क्या होगा? भारत और भारतीयों द्वारा वहां मानवीय सहायता, शिक्षा, विकास, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निवेश का क्या होगा? तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है और अभी सभी का ध्यान अपने-अपने नागरिकों को बचाने पर है, लेकिन आने वाले दिनों में व्यवस्थित ढंग से सोचना होगा कि ताकत और पैसे के भूखे आतंकियों के खिलाफ क्या किया जाए।

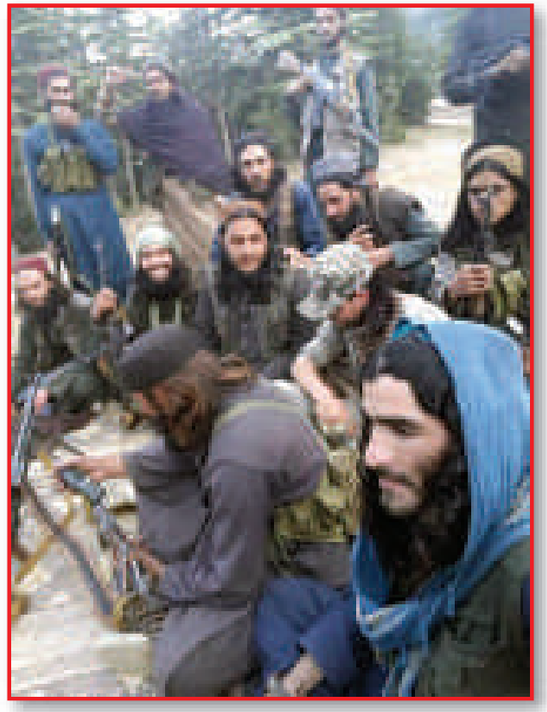

इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहना उपयुक्त है की यह खुशी की बात है कि अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी हो रही है। भारत सरकार की नींद देर से खुली लेकिन अब वह काफी मुस्तैदी दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन प्रशंसनीय है कि अफगानिस्तान के हिंदू और सिख तथा अफगान भाई-बहनों का भारत में स्वागत है। ऐसा कहकर उन्होंने सीएए कानून को नई ऊंचाईयाँ प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंजला मर्केल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन से अफगानिस्तान के मसले पर बात की। संयुक्त राष्ट्रसंघ और अंतरराष्ट्रीय मानव आयोग में भी हमारे प्रतिनिधियों ने भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। हमारे प्रधानमंत्री और प्रतिनिधियों ने अपनी बातचीत और भाषणों में कहीं भी तालिबान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने काबुल में किसी की भर्त्सना नहीं की लेकिन उन्होंने बड़े पते की बात बार-बार दोहराई। उन्होंने कहा कि हम काबुल की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह आतंकवाद को बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं देगी; वह अफगानिस्तान की जमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। ये जो बातें हमारी तरफ से कही गई हैं, बिल्कुल ठीक हैं। भारत ने चीन की तरह अमेरिका के मत्थे सैनिक वापसी और अराजकता का ठीकरा नहीं फोड़ा है और न ही उसने पाकिस्तान पर कोई हमला किया है, हालांकि पाकिस्तान तालिबान को पहले भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। इस समय भारत के लिए सही नीति यही है कि उसका रवैया रचनात्मक रहे और सावधानीपूर्ण रहे।

उ.प्र. के बाद पंजाब, उत्तराखंड में भी डूबेगी कांग्रेस?

डॉ. विजय खैरा

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की ऐसी गले की हड्डी बन गए हैं जिसे न गुटका जा सकता है न बाहर थूका जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का कद कम करने के लिए सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पर उन्होंने आते ही कांग्रेस का कद कम करना शुरू कर दिया। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। कोई भी समझदार नेतृत्व ऐसे समय में पार्टी में दो धड़े बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता पर सोनिया और राहुल गांधी ने ऐसा किया। सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का एक भी कारण समझ नहीं आता। चुनाव का समय नजदीक है सिद्धू पंजाब की राजनीति से कुछ समय से बाहर चल रहे थे। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के मुख्य मंत्रियों या नेताओं के बढ़ते कद से तकलीफ क्यों होती है उन्हें तो कहीं से कोई खतरा नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब पार्टी ने ऐसा कदम उठाया है। राहुल गांधी अपनी गलतियों से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं।

राहुल ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी इसी तरह गले की हड्डी बना लिया। उनके ही कारण मध्य प्रदेश की सरकार गयी। राहुल को जरूरत से ज्यादा दिग्गी प्रेम ने मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार मिटवा दी। दिग्गी की सलाह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को कम आंका गया। राज्यसभा की सीट दिग्गी राजा को देना थी तो देते पर सिंधिया को क्यों नहीं दी। दोनों ही लोकसभा का चुनाव हारे थे। सिंधिया के पक्ष में तो 25 से अधिक विधायक थे जबकि दिग्विजय के पास 10, 12 से अधिक नहीं थे। यदि अब दिग्गी का कद कम करते हैं तो मध्यप्रदेश में नुकसान होता है और बनाए रखते हैं तो पार्टी का नुकसान पूरे देश में हो रहा है। यही हाल सिद्धू का हो गया, यदि अध्यक्ष बनाए रखते हैं तो पूरे देश में पार्टी की छीछालेदर हो रही है उसे रोक नहीं पाएंगे। हटाते हैं तो हाईकमान के अपने निर्णय का मजाक बनने का डर है।

उत्तर प्रदेश में वैसे कांग्रेस के पास कुछ खोने को था ही नहीं। थोड़ा बहुत कुछ पा सकती थी। वो अपनी गलतियों से खो दिया। प्रदेश को जब एक मजबूत अनुभवी अध्यक्ष की तलाश थी ऐसे में अजय कुमार लल्लू को बनाये रखने से पार्टी को फिर करारी हार मिल सकती है। न वे संघर्षशील नेता साबित हुए न ही कार्यकर्ताओं में जोश भर सके और न ही बूथ स्तर पर कोई कार्रवाई कर सके। पहले से संगठन और भी कमजोर हो गया। प्रदेश में कोई नेता नहीं प्रियंका गांधी के अतिरिक्त पर वे भी इतने समय के बाद भी उत्तर प्रदेश में कोई अपनी छवि में राजनीतिक निखार नहीं ला सकी। उनके भरोसे उ.प्र. के चुनाव पार्टी लड़ना चाहती है तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उनके पास करिश्माई नेतृत्व नहीं है न ही राजनैतिक सूझ-बूझ है। केवल इंदिरा जी से मिलती शक्ल है उसका लाभ

नवजोत सिंह सिद्धू

हरीश रावत के साथ कैप्टेन अमरिन्दर सिंह

कितना मिल पाएगा यह पिछले चुनाव ने बतला दिया। यहां तक कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा सीट हार गये जहां वे चुनाव संभाले हुए थी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पार्टी मुंह की खाने वाली है।

मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। स.पा. नेता आजम खान के जेल जाने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी परवाह नहीं की, इस कारण बहुत से मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव के विरोध में बयानबाजी की है। पश्चिमी जिलों के नेताओं ने तो उन्हें अवसरवादी एवं स्वार्थी कहा है और उन्हें चुनाव में मजा चखाने की बात कही है। ऐसे हालातों में पश्चिमी उ.प्र. का और विशेषकर आजम खान को नेता मानने वाला मुस्लिम वोट स.पा. को नहीं मिलेगा। इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट स.पा. से छिटका था इसलिए बहुजन समाज पार्टी के 10 लोकसभा सदस्य चुने गए थे जबकि स.पा. के उससे आधे यानी 5, वो भी मुलायम सिंह और अखिलेश को मिलाकर। पंजाब में कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर दिखाई दे रही थी, जिसके कई कारण थे। पंजाब में अकाली दल और भाजपा का गठबंधन टूट जाने के कारण कांग्रेस अपने आप को सुरक्षित मान रही थी। शायद इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने अमरिन्दर सिंह के बढ़ते कद को छाँटने के लिए उनके धुर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना कर भेजा है लेकिन ये गोट अब उलटी पड़ गई है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार का फिर से बन जाना संभव नहीं लगता है। दोनों गुटों में बात इतनी बढ़ गई है कि सिद्धू के लोग खुलकर प्रेस में अमरिन्दर सरकार को भ्रष्ट नकारा बतला रहे हैं।

मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। स.पा. नेता आजम खान के जेल जाने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी परवाह नहीं की, इस कारण बहुत से मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव के विरोध में बयानबाजी की है। पश्चिमी जिलों के नेताओं ने तो उन्हें अवसरवादी एवं स्वार्थी कहां है और उन्हें चुनाव में मजा चखाने को कहा है।

यही हाल उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारकर किया है। भा.ज.पा. ने जल्दी-जल्दी मुख्यमंत्री बदलकर जो नुकसान उठाना था उस नुकसान की भरपाई कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल कर दी है। चुनाव के 6 माह पहले उत्तराखंड का अध्यक्ष बदला और नए अध्यक्ष को टीम वहीं मिली जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीष रावत ने बनायी। नयी कमेटी में छांट-छांट कर सारे अपने लोगों को बड़े पद दे दिए। चलती पार्टी के पहिए को पंचर कर दिया। हरीष रावत जो पंजाब में संकट मोचन टीम के सदस्य हैं वहां तो कुछ गुल खिला नहीं पाये। यहां उन्होंने गुल खिलाने के बजाय उठती हुयी पार्टी को वापस जहां का तहां भेज दिया। पिछले चुनाव में उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। वह फिर से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। टिकट के बंटवारे में भी यही होने वाला है नया अध्यक्ष रावत की कठपुतली की तरह काम करेगा और राहुल गांधी हमेशा की तरह गच्चा खा जायेगें। सच पूछो तो उत्तराखंड में नए अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीष रावत की दुकड़ी ने भा.ज.पा. की जीत की कठिन राह को आसान कर दिया है।

आने वाले विधानसभा चुनाव का समीकरण ऐसा बन गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो भा.ज.पा. की जीत आज ही सुनिश्चित लग रही है। पंजाब में इसीलिए कांग्रेस के जीतने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अकालियों की पौ बारह हो गई है इसीलिये भाजपा का ग्राफ भी बढ़ चला है भा.ज.पा. पहले से अधिक सीटें पा सकती है। ये भी हो सकता है कि अमरिन्दर सिंह हाईकमान और सिद्धू से तंग आकर अपनी पार्टी बनाएं और अकेले दम पर चुनाव लड़े ऐसे में खिचड़ी सरकार बनेगी। पंजाब में शायद ही किसी एक पार्टी को बहुमत मिले क्योंकि गिरी से गिरी हालत में आप पार्टी भी कुछ सीटें जीतेगी और हो सकता है। भा.ज.पा. कैंप में खुशी है कि हरीष रावत ने उत्तराखंड में और नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबोने का काम कर दिया। उ.प्र. में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भा.ज.पा. सरकार बनाने के लिए पूरी अस्वस्थ है और ऐसा राजनैतिक विशेषज्ञ भी मानते है।

कल्याण सिंह

राजनीति के एक युग का अंत

प्रणय कुमार

कल्याण सिंह का देहावसान राजनीति के एक युग का अंत व अवसान है। वे भारतीय राजनीति के शिखर-पुरुष के रूप में सदैव याद आएँगें। एक साधारण शिक्षक से जननेता तक की उनकी राजनीतिक यात्रा अविस्मरणीय है। वे जनसंघ के दिनों से भारतीय राजनीति की सनातन सांस्कृतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते रहे। उन्होंने सत्ता के लिए कभी समझौता नहीं किया। न उनमें सत्ता का कोई मोह ही था। बल्कि उन्होंने ध्येयनिष्ठा के लिए सत्ता को सहर्ष ठोकर मार दी। उनके ये शब्द सदियों तक जनमानस के मन-मस्तिष्क में गूँजते रहेंगें कि ''सत्ता रहे या जाए, मैं मुख्यमंत्री रहूँ या न रहूँ, पर निर्दोष कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा!'' 6 दिसंबर, 1992 को उत्तरप्रदेश के तत्कालीन डीजीपी एस.एम.त्रिपाठी भागे-भागे आए और उनसे कहा कि ''कार सेवक विवादित ढाँचे को तोड़ रहे हैं, फायरिंग की परमिशन चाहिए।'' मुख्यमंत्री ने पूछा कि ''गोली चलाने पर कितने लोग मारे जाएँगें?'' डीजीपी बोले- ''बहुत लोग मारे जाएँगें।'' कल्याण सिंह ने कहा ''आँसू गैस चलाइए या लाठीचार्ज करिए, लेकिन फायरिंग की परमीशन नहीं दे सकता। आप चाहें तो मैं कागज़ पर लिखकर दे सकता हूँ कि मैंने अनुमति नहीं दी।'' उस दिन जिस समय विवादित ढाँचा ढ़हाया जा रहा था, वे टीवी देख रहे थे, कुछ विचलित भी थे, लेकिन जैसे ही आखिरी ईंट गिरी, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री वाला राइटिंग पैड मंगाया और त्यागपत्र लिख दिया। उन्होंने बाहर आकर यह अति संक्षिप्त किंतु ऐतिहासिक वक्तव्य दिया- ''यह सरकार श्रीराम के मंदिर के ही नाम पर बनाई गई थी, श्रीराम के मंदिर के लिए मैं ऐसी कई कुर्सियाँ त्याग सकता हूँ।'' और सचमुच उन्होंने उत्तरप्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद से

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए

त्यागपत्र देने में रंचमात्र संकोच नहीं दिखाया। राजनीति में सामूहिक ध्येय एवं महान संकल्प के लिए सत्ता का ऐसा परित्याग दुर्लभ है। ऐसे दृष्टांत स्वतंत्र भारत में खोजने पर भी अन्य नहीं मिलते। जनसाधारण के स्वाभाविक ज्वार की भी नैतिक जिम्मेदारी लेने का ऐसा दृष्टांत, ऐसा साहस - संघर्षों में तपे, ज़मीन से उठे उनके जैसे जननेता में ही देखने को मिल सकता है। त्याग, साहस, संघर्ष, संकल्प एवं संगठन-कौशल के पर्याय थे वे। ढाँचा-ध्वंस के पश्चात सीबीआई द्वारा दायर याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह अयोध्या दौरे पर गए थे और वहाँ जाकर रामलला के दर्शन करते हुए मंदिर-निर्माण की शपथ ली थी। सदियों के संघर्ष व आस्था का पुनीत परिणाम तथा देश-दुनिया में फैले कोटि-कोटि भारतवासियों का चिर-प्रतीक्षित स्वप्न यदि आज श्रीराम के भव्य मंदिर के रूप में सजीव-साकार होने जा रहा है तो उसकी नींव में कल्याण सिंह जैसे नायकों का त्याग एवं संघर्ष भी है। श्रीराम केवल किसी समुदाय-विशेष के आस्था के केंद्र बिंदु नहीं, वे विश्व-मानवता के आदर्श व पथ-प्रदर्शक हैं। उनके दर्शनार्थ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उनके जीवन-चरित से तो प्रेरणा मिलेगी ही मिलेगी। पर आस्था और श्रद्धा के इस सबसे बड़े केंद्र को बचाने के लिए किए जाने वाले सुदीर्घ संघर्ष, त्याग और बलिदान भी कम प्रेणादायी नहीं हैं। भला किस आस्थावान भारतीय के स्मृति-पटल से कारसेवा के दौरान मारे गए रामभक्त कोठारी बंधु की, पुलिस की लाठी से चोटिल एवं लहूलुहान अशोक सिंहल जैसे महानायक की छवि ओझल हो सकती है! महत उद्देश्यों एवं ऊँचे ध्येय को समर्पित जीवन भुलाए नहीं भूलते!

कल्याण सिंह स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जनांदोलन श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ और नायक मात्र ही नहीं थे। उन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा तय की, राजनीति में सफलता के प्रचलित मानक एवं प्रतिमान बदले। उन्होंने दशकों से उपेक्षित एवं तिरस्कृत हिंदू अस्मिता, हिंदू चेतना को मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा माना और बनाया। हिंदू होना और हिंदू होने के गौरवबोध को मन में धारण करना- इस देश में पिछड़ेपन का द्योतक मान लिया गया था। स्वातंत्र्योत्तर भारत में क्षद्म धर्मनिरपेक्षता एवं कथित बौद्धिकता की ऐसी हवा चला दी गई, जिसमें हिंदू होना और स्वयं को हिंदू मानना राष्ट्रीय शर्म का विषय बना दिया गया। परंतु कल्याण सिंह समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग से आए पहले ऐसे व्यापक जनाधार वाले राजनेता थे, जिन्होंने कभी ऐसे विरोधी वायुमंडल की चिंता नहीं की। उन्होंने कभी जातिवादी या पिछड़े-अगड़े की राजनीति नहीं की। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए छोटी-छोटी अस्मिताओं में बंटी-कटी संकीर्ण-संकुचित उत्तर भारतीय राजनीति को उन्होंने बड़ी अस्मिता, बड़ी चेतना से जोड़ा। जातियों में बँटे समाज और राजनीति को वे श्रीराम जन्मभूमि के जनांदोलन के माध्यम से महत एवं बृहत्तर ध्येय से जोड़ पाने में असाधारण रूप से सफल रहे। उन्होंने हिंदू अस्मिता को ही भारत की सांस्कृतिक अस्मिता माना। हिंदू संस्कृति का मतलब उनके लिए निश्चित विश्वास एवं विशेष उपासना-पद्धत्ति से कभी नहीं रहा। वे जानते और मानते थे कि मज़हब बदलने से पुरखे व संस्कृति नहीं बदलती। मज़हब चाहे भिन्न हो, उपासना पद्धत्ति चाहे भिन्न हो पर भारत भूमि पर रहने वाले भारतवासियों की संस्कृति एक है। वह सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी है। कोई उसे हिंदू कहता है, कोई भारतीय, कोई सनातन। परंतु भारत की जिस सनातन एवं गौरवशाली परंपरा के कारण पूरी दुनिया उसे विश्वगुरु मानती आई है, वह हिंदू संस्कृति और परंपरा ही है। इसे स्वयं मानना एक बात है, पर जनमानस के हृदय में उतार पाना दूसरी बात। वे इस भाव को समाज के शोषित-वंचित-पिछड़े वर्गों के हृदय में उतार पाने में क़ामयाब रहे।

नब्बे के दशक का कदाचित ही कोई ऐसा युवा हो, जो कल्याण सिंह की शैली, निर्भीकता एवं स्पष्टवादिता से प्रभावित न रहा हो, जिसकी चेतना कल्याण सिंह के तुकबंदीयुक्त राजनीतिक भाषणों-उद्बोधनों से प्रेरित-उद्वेलित न हुई हो। वे बिना लाग-लपेट के स्पष्ट एवं खरा बोलते थे। यही उनकी ताक़त थी। उनकी छवि एक सख्त, स्वच्छ, सुयोग्य एवं ईमानदार मुख्यमंत्री की थी। उन्होंने शासन-प्रशासन एवं उत्तरप्रदेश की व्यवस्था को लालफीताशाही के चंगुल से मुक्त किया। वे कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते थे। चाहे नकल अध्यादेश हो, एक-एक करके चार विधायकों को जेल भेजने का साहसिक निर्णय हो या अपराधियों पर नकेल कसना हो- उन्होंने लोकप्रियता, वोट-बैंक, जातिवादी जोड़-तोड़ के गणित की परवाह किए बिना निर्णय लिए। वे दो बार उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान के राज्यपाल रहे। वे भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने साइकिल और पोस्टकार्ड युग में दल को खड़ा किया था। उनके सुंदर, सुडौल, सुगढ़ अक्षरों में लिखे पोस्टकार्ड उस दौर के कार्यकर्त्ताओं ने आज भी सहेजकर रखे हैं। उन्हें ढाँचा गिरने के कारण एक दिन के जेल की सजा भी भोगनी पड़ी थी। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। आपातकाल के दौरान वे 21 माह तक जेल की काल-कोठरी में कैद रहे थे। वे ज़मीन से उठे और संघर्षों में तपे और पले-बढ़े थे। उनकी इच्छाशक्ति अदम्य थी। उनका अंतिम स्वप्न अपने जीवन काल में श्रीराम-मंदिर का भव्य निर्माण देखना था। उनका यह स्वप्न भले अधूरा रह गया हो, पर वे उन सौभाग्यशालियों में से एक थे, जिसके जीवन-काल में श्रीराम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो चुका था। उनकी अंतिम इच्छा भाजपा के झंडे में लिपटकर दुनिया से प्रस्थान करने की थी, सो प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से पूर्ण हुई। उपचार के दौरान चिकित्सालय मिलने आने वाले परिचितों-राजनीतिज्ञों का अभिवादन वे जय श्रीराम बोलकर करते थे। न केवल उत्तरप्रदेश, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में जनसंघ-भाजपा की सफ़लता का विस्तृत इतिहास जब कभी लिखा जाएगा, उसमें कल्याण सिंह के योगदान का अध्याय स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा।

उमेश उपाध्याय

तालिबान और भारत

आशंका नहीं संकल्प का समय

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भय, आशंका और अनिश्चय का माहौल हैं। अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का हर सभ्य देश तालिबान को लेकर फिक्रमंद दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि अभी तक किसी देश ने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। तालिबान ने बयान ज़रूर दिए हैं कि वे अब पहले जैसे नहीं है, पर उनकी बात पर यकीन मुश्किल है।

उनके बयानों के परे अफगानिस्तान से आ रही खबरें आश्वस्त नहीं करतीं। काबुल में औरतों का घर से निकलना बंद हो गया है। जीत के उपहार के तौर पर घरों की तलाशी लेकर नाबालिग बच्चियों तथा अन्य औरतों की शादी जबरन तालिबान लड़ाकों से करवाई जा रही है। कई जगहों से समर्पण करने वाली अफगान सेना के फौजियों की निर्मम हत्या की खबरें आ रहीं हैं।

भारत को जिस तरह से अपने दूतावास को बंद करके काबुल से निकलना पड़ा है वह कोई खुश होने की बात नहीं हैं। ये कोई खास शाबाशी की बात नहीं है कि हम अपने लोगों को बिना नुकसान वहां से ले आये हैं। आखिर एक पडोसी देश से हमें अफरातफरी में तकरीबन भाग के आना पड़ा हो, भारत जैसे देश के लिए कोई गर्व का विषय नहीं हो सकता। पिछले कई सालों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में हमने अच्छा खासा निवेश किया था। ये निवेश सिर्फ आर्थिक संसाधनों का ही नहीं वरन हमारे संबंधों, राजनीतिक और राजनयिक पूँजी का भी था। लोग कह सकते है कि आज के हिसाब से तो वहां से निकलना ही हमारे सामने सबसे बेहतर विकल्प था।

तालिबान के कब्ज़े के बाद भारत के पास अफगानिस्तान में दो ही विकल्प थे- एक ख़राब विकल्प और दूसरा बहुत खराब विकल्प। हमने 'बहुत खराब विकल्प' की अपेक्षा 'खराब विकल्प' को चुना और बिना किसी बड़ी परेशानी के हम अपने लोगों को

निकाल लाये। ये आज के लिए संतोष की बात होगी पर हमारे दूरगामी हितों पर इसका कितना उल्टा असर होगा ये अंदाज़ा लगाने के लिए आपको कोई विशारद होने की आवश्यकता नहीं है।

सवाल है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंचे कैसे?

पिछले चालीस साल में दरअसल हमारी अफगानिस्तान नीति बेहद रक्षात्मक और पराबलम्बी रही है। जब सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो हम उसकी नीति के पिछलग्गू हो लिए थे। सोवियत संघ की गोद में बैठने का ही परिणाम था कि उसके जाने के बाद वहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं था और तालिबान के पिछले शासन में पाकिस्तान ने उसका उपयोग कर हमारे लिए सुरक्षा के गंभीर खतरे खड़े कर दिए। 9/11 के बाद हमने अपने पिछले अनुभवों से कुछ नहीं सीखा और हमने अपने सारे पाँसे अमरीका के खाने में डाल दिये। और अब जब अमरीका वहाँ से भाग रहा है तो हम भी ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए हैं।

ये समस्या इस सरकार को विरासत में ही मिली थी इसलिए मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी सीमित ही बनती है। इसके लिए पिछले चालीस साल का राजनीतिक नेतृत्व तो उत्तरदायी है ही; अगर कोई सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वे हैं, आजकल टीवी चैनलों की बहस में भाग लेने वाले और अफगानिस्तान विशेषज्ञ बनकर कागज काले करने वाले विदेश सेवा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारी। ज्ञान बखारने वाले ये कथित विदेश और सुरक्षा नीति विशेषज्ञ आज बता रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए था। इनमें से कई तो सीधे तौर पर इन मामलों को देखते रहे हैं। इनमें से एक एक को बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई जब आप कुर्सी पर बैठे थे तब आपने खुद क्या किया था? क्या आपकी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?

पिछले चालीस साल में दरअसल हमारी अफगानिस्तान नीति बेहद रक्षात्मक और पराबलम्बी रही है। जब सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो हम उसकी नीति के पिछलग्गू हो लिए थे। सोवियत संघ की गोद में बैठने का ही परिणाम था कि उसके जाने के बाद वहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं था और तालिबान के पिछले शासन में पाकिस्तान ने उसका उपयोग कर हमारे लिए सुरक्षा के गंभीर खतरे खड़े कर दिए।

अब इन्हीं में से अधिकतर 'विशेषज्ञ' देश में डर, अनिश्चितता और आशंका का माहौल पैदा कर रहे हैं। मानो, तालिबान के आने से न जाने क्या हो जाएगा? ये बात सही है कि चार दशक की गलत नीतियों के कारण भारत आज अफगानिस्तान को लेकर तकरीबन शून्य की स्थिति में खड़ा हो गया है। ये भी सही है कि पड़ोस में जब मध्ययुगीन बर्बर मानसिकता से संचालित धर्मांध इस्लामी जिहादियों को अफगानिस्तान के रूप में एक पूरा देश मिल गया है तो हमारी सुरक्षा चुनौतियाँ विकट हो गयी हैं। पर ये भी याद रखने की बात है ये भारत सन 1999-2000 का भारत नहीं है।

आज भारत को दो चीज़ों की ज़रुरत है। पहला है धैर्य और दूसरा है संकल्प। हमारी विदेश नीति के कर्ता धर्ताओं को अब धैर्यपूर्वक नयी अफगानिस्तान नीति पर काम करना चाहिए। अफगानिस्तान नीति को आरामकुर्सी पर बैठकर व्याख्यान देने वाले इन विशेषज्ञों से लेकर जमीन पर काम करके भीतरी पैठ बनाने वाले लोगों को सुपुर्द करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वे भारतीय विदेश सेवा से ही हों।

अब तो संयम के साथ ईंट पर ईंट जमाते हुए धीरज, मनोयोग और मेहनत से अफगानी समाज में उन लोगों के साथ ताल्लुक कायम करने की ज़रुरत है जिनका भारत से भावनात्मक रिश्ता है। ऐसे ही लोग भारत के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं यह काम एक दो बरस नहीं बल्कि दशकों तक करना पड़ेगा। जिस तरह अफगानिस्तान में भारत का खेल बिगड़ने में कोई चार दशक लगे हैं, उन्हें सुधारने के लिए भी दशकों का धैर्य चाहिए।

साथ ही भारत को पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा विवाद की लकीर को भी गहरा करने का काम करना चाहिए। डूरंड रेखा के दोनों पार बसे पख्तूनों को मिलाकर एक पख्तून रियासत की योजना 1947 से कई लोगों के मन में रही है। यों भी तालिबान भी डूरंड रेखा को मंज़ूर नहीं करते। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कश्मीर मसले पर तालिबान उनका साथ देंगे। हालाँकि तालिबान के बयान इससे भिन्न हैं। पर हम किसी ग़लतफहमी में नहीं रह सकते। इसलिए पाकिस्तान सेना और जिहाद समर्थक पाकिस्तानी आतंकी गुटों को पता रहना चाहिए कि भारत में दखल देने का नतीजा उल्टा भी हो सकता है। भारत हमेशा रक्षात्मक क्यों रहे? वह एक अलग पख्तून रियासत का पाँसा क्यों नहीं फेंक सकता?

साथ ही अब भारत को संकल्प भी करना है। वो है सतत चौकन्ना रहकर किसी भी संभावित कुटिलता का उत्तर बुद्धिमत्तापूर्ण वीरता से देने की तैयारी करने का। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों की हवा बालाकोट के आक्रामक तरीके से देश का मौजूदा मज़बूत नेतृत्व निकाल चुका है। उसी तरह पाशविक बर्बरता की हद तक जाने वाले आसन्न कट्टरपंथी इस्लामिक खतरे से निपटने का माद्दा, हिम्मत और क़ाबलियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा नेतृत्व में है। इसका सबको भरोसा रहना चाहिए।

तालिबानी कब्जे में बदकिस्मत अफगानिस्तान

उमेश चतुर्वेदी

अफगानिस्तान में इन दिनों अफरातफरी का माहौल है। वजह है अफगानिस्तान में ठीक बीस साल बाद उस तालिबान की वापसी, जिसे अमेरिका की अगुआई में नाटो देशों की सेनाओं ने खदेड़ दिया था। तालिबान का अतीत जैसा रहा है, जिस तरह की उसकी कारस्तानियां रहीं हैं, उसके बाद अफरातफरी मचनी ही थी। पिछले साल दोहा में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए समझौते के बाद तालिबान को वैसे तो 14 अगस्त तक ना सिर्फ काबुल आना था, बल्कि उसे शांति पूर्वक सत्ता का हस्तांतरण करना था। लेकिन उसने पहले ही काबुल में ना सिर्फ कब्जा कर लिया, बल्कि वहां बल पूर्वक सत्ता भी हासिल कर ली। उसके डर से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही अफगानिस्तान छोड़कर कतर भाग गए।

इसके बाद से अफगानिस्तान का हर नागरिक अफगानिस्तान छोड़ने की फिराक में जुट गया है। काबुल हवाई अड्डे की ओर लोग लगातार जा रहे हैं। जिन्हें रोकने के लिए तालिबान के लड़ाके फायरिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जिसे जहां मौका मिल रहा है, उसी इलाके से सीमा पार करने की कोशिश में है। कुछ लोग उजबेकिस्तान निकल गए तो भारी संख्या में लोग पाकिस्तान की ओर आ रहे हैं। हवाई जहाज से या तो लोग कतर जा रहे हैं या फिर भारत आ रहे हैं। कुछ ने मास्को का रूख किया तो कुछ ने कहीं ओर का। अफगानी लोगों के डर की वजह भी है। दरअसल अपने पिछले शासन के दौरान तालिबान ने कड़े इस्लामिक कानून लागू किए थे। चूंकि ऐसे ही कानून उसने 1996 से 2001 के बीच के अपने शासन काल में भी लागू किए थे। इसलिए यह डर अस्वाभाविक भी नहीं है। तब तालिबान ने बच्चियों के स्कूल जाने और महिलाओं के बाहर काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ ही उनके लिए बुर्का पहनना जरूरी कर दिया था। शरीया कानूनों के मुताबिक तालिबान शासन के दौरान महिलाओं के घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ अपना पुरुष रिश्तेदार रखना भी जरूरी होता था। तालिबान ने तब संगीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी थी। उस दौरान कड़ी सजाएं भी दी जाती थीं। चोरी के आरोप में लोगों के हाथ काट लिए जाते थे तो बेवफाई की सजा सार्वजनिक रूप से पत्थर मारना थी।

दुनियाभर में हो रही आलोचनाओं और आशंकाओं को देखते हुए तालिबान ने इस बार अपना नरम चेहरा दिखाने की कोशिश की है। काबुल पर कब्जे के बाद यहां के स्थानीय चैनल टोलो न्यूज पर उसकी महिला एंकर बेहेश्ता को तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल हक हम्माद ने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में तालिबान प्रवक्ता अब्दुल हक हम्माद ने दावा किया कि तालिबान इस बार लोगों का दिल और दिमाग जीतेगा। हम्माद ने यहां तक दावा किया कि तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान शांति बहाली की तरफ बढ़ेगा। गौरतलब है कि हम्माद तालिबान के दुबई स्थित दफ्तर में रहता है। उसके पास ऑस्ट्रेलिया की भी नागरिकता है। इस इंटरव्यू में उसने कहा कि उनके लिए लोगों का दिल और दिमाग जीतना और अंतरराष्ट्रीय लोगों को यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि वे वैध हैं और उनके साथ कोई भी काम कर सकता है। उसने यह भी कहा कि तालिबान शासन मीडिया को काम करने की आजादी देगा।

लेकिन यह सारी बातें थोथी साबित हुईं। अगले ही दिन तालिबान के आतंकियों ने यहां के टीवी चैनलों पर कब्जा कर लिया और वहां ड्यूटी पर आई महिलाओं को वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, काबुल छोड़कर भाग रहे लोगों पर गोलीबारी की। तालिबान लड़ाके कहीं भी-कभी भी गोलीबारी कर दे रहे हैं।

दोहा समझौते के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ना है। लेकिन अब तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फरमान सुना दिया है। तालिबान के इस कदम से माना जा रहा है कि वह देर से ही सही, अपने उसी पुराने रंग में लौट आएगा, जैसा रंग उसका 1996 से 2001 के शासन के बीच रहा है। जिसमें उसने एक तरह से मध्ययुगीन शासन व्यवस्था स्थापित की थी। इसी शासन के दौरान उसने बामियान की प्रसिद्ध बुद्ध मूर्तियां उड़ा दी थीं। इस बार भी उसका वही रूप देखने को मिल रहा है। उसके लड़ाकों ने गजनी स्थित इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र को ढहा दिया है।

तालिबान पर भारत ने अपना रूख अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन अतीत में भारत के साथ तालिबान का जो रवैया रहा है, वह आशंकित करने के लिए काफी है। वैसे तो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत तीन लाख करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार देखो और इंतजार करो की नीति पर अमल कर रहा है। वैसे कुछ खबरें आई हैं, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां सक्रिय कश्मीरी आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लौट आए हैं और वहां उन्होंने विजय जुलूस निकाला है।

भारत से चीन और पाकिस्तान के रिश्ते छुपे नहीं हैं। सबको पता है कि चीन और पाकिस्तान भारत के प्रति कैसी धारणा रखते हैं। जिस तरह तालिबान को समर्थन देने का चीन ने ऐलान किया है और हाल के दिनों में ईरान ने भारत से जिस तरह दूरी दिखानी शुरू की है, उससे भारत की सीमाओं में चुनौती बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। चीन, पाकिस्तान, ईरान और अब अफगानी तालिबान मिलकर भारत के खिलाफ कुचक्र रच सकते हैं। इसके लिए भारत को सचेत रहना होगा। दिसंबर 1999 में जिस तरह काठमांडू से दिल्ली आ रहे भारतीय विमान का अपहरण हुआ था, वह भारत नहीं भूल पाया है। उसके पीछे तालिबान का भी हाथ रहा। फिर तालिबान के आतंकी पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते भारतीय कश्मीर में आतंकी दखलंदाजी करने की कोशिश करेंगे। शायद यही वजह है कि भारत की अभी पूरी कोशिश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों की सकुशल वापसी पर केंद्रित है। वैसे तालिबान को भी पता होगा कि आज का भारत 1999 का भारत नहीं है और ना ही अब भारत में गठबंधन की ऐसी सरकार है, जो दबावों में काम करने को मजबूर थी। इसलिए तालिबान भी भारत के खिलाफ सोच-समझकर ही कदम उठाने की सोचेगा।

सबसे हैरत की बात यह है कि अफगानिस्तान की सेना में तीन लाख से ज्यादा सैनिक कार्यरत थे। जब अमेरिकी सेनाओं की वापसी होने लगी तो तालिबान ने जिस तरह हमले शुरू किए, तब तमाम सैनिक और अफगानी मामलों के जानकार दावा कर रहे थे कि अफगान सेना के सामने सत्तर-पचहत्तर हजार की संख्या वाले तालिबान टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारों के मुताबिक, अफगानी सैनिकों के समर्पण की कई वजहें रहीं। दरअसल माना जा रहा है कि बाहरी मदद के चलते अफगानिस्तान में इफरात पैसा आ रहा था। वहां आर्थिक कदाचार पर लगाम का कोई माकूल इंतजाम नहीं था। भ्रष्टाचार का आरोप वहां के गृहमंत्री तक पर भी लग रहा था। चूंकि राजनीतिक नेतृत्व में भ्रष्टाचार चरम पर था, लिहाजा सैनिकों को वह लड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया। जब देश में तालिबान ने सक्रियता बढ़ाई, तब भ्रष्टाचार की वजह से सैनिकों को वक्त पर गोला-बारूद तक नहीं मिल पा रहा था। सुरक्षा बलों को ना तो पर्याप्त वेतन मिल रहा था और ना ही वक्त पर ठीक खाना। जानकार बताते हैं कि ज्यादातर सैनिकों की तनख्वाह महज पांच हजार रूपए के बराबर थी। वह भी भ्रष्टाचार की वजह से वक्त पर नहीं मिल पाता था। ऐसे में जैसे ही तालिबान ने दबिश बढ़ाई, सुरक्षा बलों ने मोर्चा छोड़ दिया।

यह बात और है कि तालिबान अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में विरोध तेज हो गया है। अहमद शाह मसूद के बेटे शाह मसूद और उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह की अगुआई में पंजशीर घाटी ने तालिबान का नेतृत्व और सरकार मानने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में इस बीच कुछ जगहों पर लोगों ने भय त्यागकर प्रदर्शन भी किए हैं।

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा किरकिरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की हुई है। बेशक अमेरिका का अफगानिस्तान में पांव फंस गया था। लेकिन यह भी सच है कि बाइडन द्वारा सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में जिस तरह मानवता त्राहि कर रही है, उसके लिए दुनिया तो दुनिया, अमेरिका के लोग भी बाइडन को जिम्मेदार बता रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो मौका मिल गया है, यह बताने का कि उनके रहते ऐसा नहीं हो सकता था। वे कह रहे हैं कि बाइडन ने अमेरिका ने समर्पण कर दिया है। इस बीच तालिबान ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। उसकी बारह सदस्यीय शूरा यानी केंद्रीय समिति में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई समेत कई नेताओं के शामिल होने की खबर है।

इन सबके बीच अफगानी नागरिक पिस रहा है। वहां के बैंकों में कामकाज ठप्प है। आर्थिक गतिविधियां रूक गई हैं। ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हाल आदि बंद हो गए हैं। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और बाहर से जरूरी अनाज नहीं आ पा रहा है। इससे वहां महंगाई दो सौ गुना तक बढ़ गई है। इससे आम अफगानी नागरिक की जिंदगी मुहाल हो गई है। बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस दिशा में कुछ खास करता नजर नहीं आ रहा है। किसी को पता नहीं है कि चार करोड़ की आबादी और कबीलों वाले देश अफगानिस्तान के संघर्ष के दिन कितने लंबे चलेंगे ?

अफगानिस्तान में तालिबान के आगमन से उपजा वैश्विक संकट

''मुल्क कों मुल्क न रहने देने का नाम है तालिबान। धर्म की सत्ता का नया नाम है तालिबान। लाशों के ऊपर धर्म का झंडा लगा देने का नाम है तालिबान। औरतों को बुर्का पहनाकर भी नंगा कर देने का नाम है। बच्चों को मजहबी तालीम देकर भी उसे आतंकवादी बनाने का नाम है तालिबान। मानवीय संस्कारों को तिलांजलि देकर हथियारों के द्वारा जिहाद को काबिज कर देने का नाम है तालिबान''

डॉ. प्रीति

यह कहानी वहां कि है जिसे लोग अनार का देश कहते है, अनार खाइये तो उसके रस से निकला रंग मुँह लाल कर देता है, देख कर लगे कि जैसे मुँह मे खून लग गया हो और विडंबना तो देखिए यही खून इस देश का भाग्य बन गया है जी हा हम बात कर रहे है अफगानिस्तान की, जो हालहि में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया जब अमेरिकी सैनिको की वापसी से एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबानियों की भी वापसी हो गई। मसलन अमेरिका सैनिकों ने 20 साल के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयर बेस बगराम को खाली कर दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों का वापस लौटना लगातार जारी है दरअसल अमेरिका राष्ट्रपति जो बाईडेन ने इस साल की शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि 11 सितंबर 2021 से पहले अमेरिका सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जायेगा। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तय हो जाने के बाद से वहां तालिबान का कब्जा जिस तेजी से बढ़ रहा है वह पुरे विश्व के लिए बेहद चिंताजनक है। भारत के लिए ज्यादा चिंतजानक इसलिये है क्योकि भौगोलिक दृष्टि से भारत अफगानिस्तान का पडोसी देश है जिसके चलते भारत पर अफगानी पलायन का बोझ तेज़ी से बढ़ रहा है । माना जा रहा है कि साल 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इससे अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में सरकार के अस्थिर होने का खतरा है। जिसका सबूत 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को अमेरिकी वर्चस्व से खत्म करने का अलल्टीमेटम तालिबानियों द्वारा विश्व शक्ति अमेरिका को दिया जाना माना जा सकता है। स्थिती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व पटल के दो देश चीन और पाकिस्तान अब खुल कर अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन को मंजूरी देने लगे है जिससे भारत मे आतंकवाद की समस्या मे भी इज़ाफा होगा।

अमेरिका के अफगानिस्तान में दाखिल होने की कहानी 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलें से जुड़ी हुई है। 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस्लामिक आतंकवादी समूह अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को इन हमलों के लिये उतरदायी ठहराया गया था। कट्टरपंथी इस्लामवादी तालिबान, जो कि उस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था ने लादेन की रक्षा की और उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिये 9/11 हमले के एक महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध हवाई हमले ''ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम'' शुरू कर दिया। इसके पश्चात नाटो गंठबधन ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लंबी कार्रवाई के पश्चात अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक संक्रमणकालीन सरकार की स्थापना की। लेकिन अब अमेरिकी सैनिको की अफगानिस्तान से वापसी से एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबानियों का आंतक आ गया है।

पश्तों भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरूआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिको को वापस लौटा रहा था उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ माना जाता है। पश्तों आदोंलन पहले इस्लामिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सउदी अरब ने फंडिग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। जल्द ही तालिबानियों के द्वारा यह वादा किया जाने लगा कि अफगनिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाकों में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ-साथ शरीया कानून के शुद्ध प्रारूप को लागू किया जाएगा। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा, सिंतबर 1995 में तालिबानियों ने ईरान की सीमा से लगें हेरात प्रांत पर कब्जा किया इसके ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबूल पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रह बुरहानद्दीन रब्बानी को सता से हटा दिया। साल 1998 के आते-आते अफगानिस्तान के तकरीबन 90 प्रतिशत क्षेत्र पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी के परिणामस्वरुप तालिबानी कट्टरपथियों ने अफगानिस्तान में शुद्ध इस्लामी तौर तरीकों को लागू किया जैसे:

- मुस्लिम पुरूष ढाडी रखेगे और महिलाए बुर्का पहन कर ही घर से निकलेगी।
- 10 साल की लड़कियों को स्कूल जाने की मनाही।
- शरिया कानूनो का पालन नहीं करने पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा।

पश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरूआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिको को वापस लौटा रहा था उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ माना जाता है। पश्तो आंदोलन पहले इस्लामिक मदरसो में उभरा और इसके लिए सउदी अरब ने फंडिग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था।

वर्तमान में तालिबान के आगमन से अफगानिस्तान की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और एक बार फिर से तालिबान के द्वारा शरिया के शुद्ध रूप को हतियारों के दम पर स्थापित किया जा रहा है। बाहरहाल तालिबान धर्म का चोला ओड़े जिस हिंसक रूप में एक बार फिर आया है उसकी दहशत पूरे विश्व मे दिखाई दे रही है।

अमेरिका का मानना है कि तालिबान के विरुद्ध चल रहा युद्ध अजेय है। अमेरिका प्रशासन ने वर्ष 2015 में मुरी में पाकिस्तान द्वारा आयोजित तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक के लिये अपना एक प्रतिनिधि भेजा था, हालांकि मुरी वार्ता से कुछ प्रगति हासिल नहीं की जा सकी थी।

दोहा वार्ता: तालिबान के साथ सीधी बातचीत के उदेश्य से अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिये एक विशेष दूत नियुक्त किया। उन्होंने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2020 में अमेरिका और विद्रोहियों के बीच समझौता हुआ। दोहा वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने कहा था कि वह केवल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करेगा, न कि काबुल सरकार के साथ, जिसे उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। अमेरिका ने प्रकिया से अफगान सरकार को अलग रखते हुए इस मांग को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया और विद्रोहयों के साथ सीधी बातचीत शुरू की। परिणामत: अमेरिका और तालिबान के मध्य कुछ समझौते हुए जिसमे कुछ महत्वपूर्ण शर्तो को सुनिश्चित किया गया। गौरतलब है कि इस समझौते मे विवाद के चार प्रमुख पहलू रहे जिसमे, हिसां, विदेशी सैनिकों, अंतर-अफगान शांति वार्ता तथा अल-कायदा एवं इस्लामिक स्टेट (आईएस की एक अफगान इकाई) जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा अफगान धरती के उपयोग जैसी गलघोठ शर्तो को माना गया है। समझौते में तय किया गया कि अमेरिका 11 सिंतबर 2021 तक अफगनिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिको को वापस बुला लेगा और तालिबान ने हिंसा कम करने, अतंर अफगान शांति वार्ता में शामिल होने की सहमति दी।

अंत में, यह समझना भी जरूरी है कि तालिबान के आने से पूरी दुनिया के कट्टरपंथी खुश हो रहे है। भारत के कट्टरपंथी, चरमपंथी फूले नहीं समा रहें है लेकिन वो शायद यह भूल रहे है कि कट्टरपंथी वो भेड़िए है जो सिर्फ शिकार करना जानते है। वो यह नहीं देखते की यह हमारे लोग है, हमारे जैसे लोग है। हर कट्टरपंथी तभी कट्टरपंथी बनता है जब वह यह मान लेता है कि उसके जैसा कोई भी नही है । तालिबान इस दुनिया में, अनवरत संघर्ष से प्राप्त की गयी सारी चीजों को खत्म करने के उददेश्य के साथ आया है। वो समय को करीब 15 सौ साल पीछे करने आया है। जिसके विषय में केवल भारत को ही नहीं अपितु पुरे विश्व को चिंतित होने की जरुरत है। ऐसा इसलिए क्योकि धर्म खतरे में है के नारे जब-जब किसी देश मे लगते है वह वास्तव में उस देश में जिहादी हिंसा को बढ़ावा देने का पहला कदम होता है जिसके शिकार अक्सर देश के युवा और मानवतावादी समर्थको को बनाया जाता है। मसलन समझने का विषय यह है कि धर्म तो हर समय सुरक्षित रहता है लेकिन उसके खतरे में होने का नाम लेकर पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दिया जाता है। जिसका भायावह रूप इस्लामिक कट्टरतावाद के रूप मे सामने आता रहा है जिसका वर्तमान उदहारण आज अफगानिस्तान बना हुआ है।

(लेखिका, अस्सिटेंट प्रोफेसर,शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैं)

औचित्य खोते वैश्विक संगठन

इसे क्या कहा जाए कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका की सेनाएँ 20 साल तक अफगानिस्तान में रहती हैं, अफगान सिक्युरिटी फोर्सेज पर तकरीबन 83 बिलियन डॉलर खर्च करती है उन्हें ट्रेनिगं ही नहीं हथियार भी देती हैं और अंत में साढ़े तीन लाख सैनिकों वाली अफगान फौज 80 हज़ार तालिबान लड़ाकों के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देती है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति एक दिन पहले तक अपने देश के नागरिकों को भरोसा दिलाते हैं कि वो देश को तालिबान के कब्जे में नहीं जाने देंगे और फिर रात को देश छोड़कर भाग जाते हैं।

डॉ. नीलम महेंद्र

दृश्य 1: सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने ही देश से पलायन करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर हज़ारों महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की भीड़ लगी है। कई दिन और रात वो भूखे प्यासे वहीं डटें हैं इस उम्मीद में कि किसी विमान में सवार हो कर वो अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने में कामयाब हो जाएंगे। बाहर तालिबान है, भीतर नाटो की फौजें। हर बीतती घड़ी के साथ उनकी उम्मीद की डोर टूटती जा रही है। ऐसे में महिलाऐं अपनी छोटे-छोटे बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए उन्हें नाटो फ़ौज के सैनिकों के पास फेंक रही हैं। इस दौरान कई बच्चे कँटीली तारों पर गिरकर घायल हो जाते हैं।

दृश्य 2: इस प्रकार की खबरें और वीडियो सामने आते हैं जिसमें अफगानिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों को तालिबान घरों से उठाकर ले जा रहा है।

दृश्य 3: अमरीकी विमान टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ रहा है और लोगों का हुजूम रनवे पर विमान के साथ-साथ दौड़ रहा है। अपने देश को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कुछ लोग विमान के टायरों के ऊपर बनी जगह पर सवार हो जाते हैं। विमान के ऊंचाई पर पहुंचते ही इनका संतुलन बिगड़ जाता है और आसमान से गिरकर इनकी मौत हो जाती है। इनके शव मकानों की छत पर मिलते हैं।

दृश्य 4: एक जर्मन पत्रकार की खोज में तालिबान घर-घर की तलाशी ले रहा है, जब वो पत्रकार नहीं मिलता तो उसके एक रिश्तेदार की हत्या कर देता है और दूसरे को घायल कर देता है।

ऐसे न जाने कितने हृदयविदारक दृश्य पिछले कुछ दिनों में दुनिया के सामने आए। क्या एक ऐसा समाज जो स्वयं को विकसित और सभ्य कहता हो उसमें ऐसी तस्वीरें स्वीकार्य हैं? क्या ऐसी तस्वीरें महिला और

बाल कल्याण से लेकर मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बने तथाकथित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के औचित्य पर प्रश्न नहीं लगातीं?

क्या ऐसी तस्वीरें अमरीका और यूके समेत 30 यूरोपीय देशों के नाटो जैसे तथाकथित वैश्विक सैन्य संगठन की शक्ति का मजाक नहीं उड़ातीं?

इसे क्या कहा जाए कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका की सेनाएँ 20 साल तक अफगानिस्तान में रहती हैं, अफगान सिक्युरिटी फोर्सेज पर तकरीबन 83 बिलियन डॉलर खर्च करती है उन्हें ट्रेनिगं ही नहीं हथियार भी देती हैं और अंत में साढ़े तीन हज़ार लाख सैनिकों वाली अफगान फौज 80 हज़ार तालिबान लड़ाकों के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देती है? वहां के राष्ट्रपति एक दिन पहले तक अपने देश के नागरिकों को भरोसा दिलाते हैं कि वो देश तालिबान के कब्जे में नहीं जाने देंगे और रात को देश छोड़कर भाग जाते हैं।

तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान की सत्ता पर ही काबिज़ नहीं होता बल्कि आधुनिक अमरीकी हथियार, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों से लेकर दूसरे सैन्य उपकरण भी तालिबान के कब्जे में आ जाते हैं।

अमरीकी सेनाओं के पूर्ण रूप से अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ही यह सब हो जाता है वो भी बिना किसी संघर्ष के। ऐसा नहीं है कि सत्ता संघर्ष की ऐसी घटना पहली बार हुई हो। विश्व का इतिहास सत्ता पलट की घटनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन मानव सभ्यता के इतने विकास के बाद भी इस प्रकार

भारत इस चुनौती से निपटने में सैन्य से लेकर कूटनीतिक तौर पर सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में वो अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति का प्रदर्शन सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद समेत धारा 370 हटाने जैसे अनेक अवसरों कर चुका है। लेकिन असली चुनौती तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनिसेफ जैसे वैश्विक संगठनों के सामने उत्पन्न हो गई है।

की घटनाओं का होना एक बार फिर साबित करता है कि राजनीति कितनी निर्मम और क्रूर होती है।

अफगानिस्तान का भारत का पड़ोसी देश होने से भारत पर भी निश्चित ही इन घटनाओं का प्रभाव होगा। दरअसल भारत ने भी दोनों देशों के सम्बंध बेहतर करने के उद्देश्य से अफगानिस्तान में काफी निवेश किया है। अनेक प्रोजेक्ट भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में चल रहे थे। सड़कों के निर्माण से लेकर डैम, स्कूल, लाइब्रेरी यहाँ तक कि वहाँ की संसद बनाने में भी भारत का योगदान है। 2015 में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के संसद भवन का उद्घाटन किया था जिसके निर्माण में अनुमानत: 90 मिलियन डॉलर का खर्च आया था।

लेकिन आज अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज़ है जो एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसे पाकिस्तान और चीन का समर्थन हासिल है।

भारत इस चुनौती से निपटने में सैन्य से लेकर कूटनीतिक तौर पर सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में वो अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति का प्रदर्शन सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद समेत धारा 370 हटाने जैसे अनेक अवसरों कर चुका है लेकिन असली चुनौती तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनिसेफ, जैसे वैश्विक संगठनों के सामने उत्पन्न हो गई है जो मानवता की रक्षा करने के नाम पर बनाई गई थीं लेकिन अफगानिस्तान की घटनाओं ने इनके औचित्य पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

दरअसल राजनीति अपनी जगह है और मानवता की रक्षा अपनी जगह। क्या यह इतना सरल है कि स्वयं को विश्व की महाशक्ति कहने वाले अमरीका की फौजों के रहते हुए वो पूरा देश ही उस आतंकवादी संगठन के कब्जे में चला जाता है जिस देश में वो उस आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए 20 सालों से काम कर रहा हो? अगर हाँ, तो यह अमेरिका के लिए चेतावनी है और अगर नहीं तो यह राजनीति का सबसे कुत्सित रूप है। एक तरफ़ विश्व की महाशक्तियां इस समय अफगानिस्तान में अपने स्वार्थ की राजनीति और कूटनीति कर रही हैं तो दूसरी तरफ ये संगठन जो ऐसी विकट परिस्थितियों में मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं की रक्षा करने के उद्देश्य से आस्तित्व में आईं थीं वो अफगानिस्तान के इन मौजूदा हालात में निर्थक प्रतीत हो रही हैं।

(लेखिका वरिष्ठ स्तम्भकार हैं)

अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव

नीलाभ कृष्णा

कहते हैं की *बर्बाद ए गुलिस्तां करने को एक उल्लू काफी है, यहाँ तो हर शाख पर उल्लू बैठे हैं।* अफगानिस्तान की भी अभी यही हालत है। पिछले बीस सालों से जो भी विकास की सड़कें अफगानिस्तान ने देखी थी, वह फिर से ज़मींदोज होने की कगार पर है। तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुका है बस इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। तालिबान के एक अधिकारी ने कहा है कि विद्रोही संगठन जल्द ही काबुल स्थित राष्ट्रपति परिसर से अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाने की घोषणा करेगा। गौरतलब यह है की 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद, अमेरिका नीत बलों द्वारा अफगानिस्तान से तालिबान को अपदस्थ करने के लिए शुरू किए गए हमलों से पहले भी आतंकी संगठन ने युद्धग्रस्त देश का नाम इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान रखा हुआ था।

हिन्दुकुश की पहाड़ियों से घिरे इस खूबसूरत मुल्क को उसके रहबरों ने इस पैमाइश के वक्त उसका साथ छोड़ दिया। अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मुहिब और राष्ट्रपति फजल महमूद फाजली के प्रशासनिक कार्यालय के प्रमुख के साथ अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के लिए रवाना हुए। कुछ विधायक इस्लामाबाद भी भाग गए हैं। इससे पहले, अफगान संसद के अध्यक्ष मीर रहमान रहमानी, यूनुस कनुनी, मुहम्मद मुहाक, करीम खलीली, अहमद वली मसूद और अहमद जिया मसूद इस्लामाबाद भाग गए, अफगान मीडिया ने बताया। राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने एक वीडियो क्लिप में कहा कि पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया।

तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और सुरक्षा भी फेल हो गई, क्योंकि हजारों लोगों ने रनवे पर कब्जा कर लिया और हर कोई जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। अफगान में तख्तापलट के बाद हजारों विदेशी भी फंस गए। भारतीय राजदूत और आईटीबीपी के 150 जवान भी काबुल में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स के 2 प्लेन भेजने पड़े। दरअसल दशकों तक चले संघर्ष और युद्ध के बाद आखिरकार अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो गया और महज 24 घंटे में अफगानिस्तान पर तालिबान का राज कायम हो गया।

तालिबानी 20 साल बाद काबुल की सत्ता पर काबिज हुए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं की अफगानिस्तान करीब 20 साल पीछे चला गया है। अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों से लेकर अब तक के बीस सालों में ना सिर्फ अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से आजाद कराया गया बल्कि इन दो दशकों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में लाखों-करोड़ों डॉलर खर्च किए। तालिबान से लड़ाई में हजारों अमेरिकी और अफगानी सैनिकों ने शहादत दी, मगर अब एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से ऐसा लग रहा है जैसे सारा संघर्ष व्यर्थ हो गया। तालिबान से अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग का परिणाम शून्य निकला, क्योंकि जिस तालिबान से अमेरिका 20 साल तक लड़ा वो तालिबान अमेरिकी सेना की वापसी के बाद 44 दिन के अंदर ही काबुल पहुंच गया।

सुपरपावर निकला फिसड्डी

यह न सिर्फ देखने बल्कि सोचने वाली बात भी है की जिस अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखा, अरबों डॉलर खर्च कर अफगानी फौज को टफ ट्रेनिंग देने का ढोल पीटता रहा, आधुनिक हथियार दिए, अल्ट्रा मॉडर्न साजो सामान दिया उसके लौटते ही सारी कहानी ही पलट गयी। अमेरिका के सारे दावे धरे रह गए। सुपरपावर फिसड्डी साबित हुआ। पिछले 20 साल में काबुल से खदेड़े गए तालिबानी एक बार फिर काबुल की गद्दी पर काबिज हो गए, लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि ये सब कुछ महज 44 दिनों के अंदर हो गया।

जानकारों के मुताबिक अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान बिजली की रफ्तार से काबुल में बने सत्ता के महल में दाखिल हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत इससे भी पहले हुई। 14 अप्रैल को जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दुनिया को बताया कि अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से वापस लौटेगी। बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की धरती छोड़ देंगे और 1 मई, 2021 को अमेरिका और नाटो ने अपने 9,500 सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया, जिनमें से 2,500 अमेरिकी सैनिक थे।

2 मई को अचानक ही अमेरिकी सैनिक कंधार एयरबेस को खाली कर निकल लिए। इसके साथ ही अमेरिकी फौज के लौटने की रफ्तार तेज हो गई। 2 जुलाई को बगराम एयरबेस, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के संचालन का सबसे अहम केंद्र था उसे अफगान बलों को सौंप दिया गया। और यही वह तारीख थी जब पिछले दो दशकों से सत्ता से बेदखल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग शुरू कर दी।

चूँकि बगराम एयरबेस राजधानी काबुल से एक घंटे की दूरी पर ही स्थित है और उसके खाली होते ही तालिबानियों को शह मिली और उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे की भीषण जंग छेड़ दी और इसके साथ ही अमेरिका का सारा संघर्ष और तमाम बलिदान अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बेकार साबित होने लगा।

यह न सिर्फ देखने बल्कि सोचने वाली बात भी है की जिस अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखा, अरबों डॉलर खर्च कर अफगानी फौज को टफ ट्रेनिंग देने का ढोल पीटता रहा, आधुनिक हथियार दिए, अल्ट्रा मॉडर्न साजो सामान दिया उसके लौटते ही सारी कहानी ही पलट गयी। अमेरिका के सारे दावे धरे रह गए। सुपरपावर फिसड्डी साबित हुआ।

कैसे किया कब्ज़ा?

टीवी9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ''अमेरिकी सेना के हटते ही सबसे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में ग्रामीण इलाके को कब्जा किया और फिर प्रांतीय राजधानियों की ओर बढ़ने लगे। हालांकि अफगानिस्तान सेना की जांबाजी किसी काम नहीं आयी। जरांज तालिबान के नियंत्रण में आने वाली पहली प्रांतीय राजधानी थी, जिसके बाद तालिबानी आतंकी आगे बढ़ते गए और एक-एक प्रांत पर कब्जा करते चले गए। बीते 10 दिन में तालिबान की रफ्तार और तेज हुई। 8 अगस्त को तालिबान ने प्रांतीय राजधानी सर-ए-पुल, कुंदूज, तालोकान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। 13 अगस्त को तालिबान को सबसे बड़ी सफलता मिली, उसने अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। 14 अगस्त को चौथे बड़े शहर मजार-ए-शरीफ पर तालिबान का कब्जा हो गया।''

15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो गया, लेकिन यहां सवाल ये है कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने इतनी जल्दी फंदा कैसे कस दिया? तालिबान में ऐसा क्या

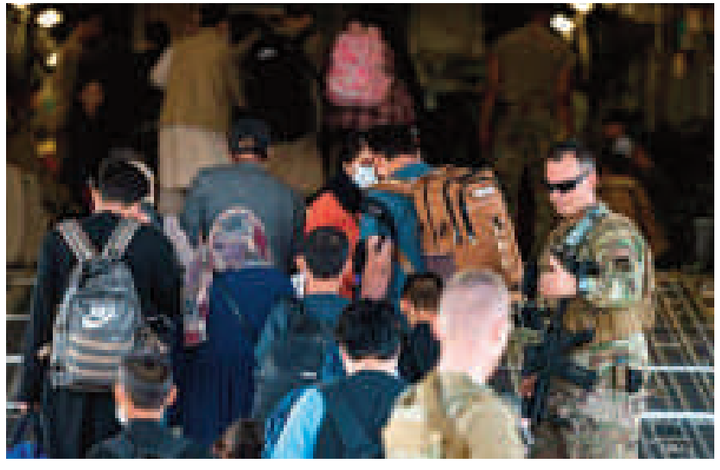

है, जिसने देखते ही देखते एक मुल्क की सत्ता को रौंद दिया? इन सारे सवालों के जवाब के मूल जड़ में हैं अफगान नेता। अफगान नेताओं ने तालिबान से समझौता कर अफगानिस्तान का भविष्य तालिबान को सौंप दिया। तालिबान ने सभी बड़े शहरों में स्थानीय नेताओं को इसके लिए राजी कर लिया कि वो अपने इलाके के सैनिकों को लड़ाई ना करने के लिए कहें। इस बात की तस्दीक कंधार के गवर्नर रोहुल्ला खानजादा ने भी की, जिनके मुताबिक नेताओं ने सैनिकों से लड़ाई ना करने का आग्रह किया और कंधार जैसा बड़ा शहर बिना लड़ाई के तालिबान के नियंत्रण में चला गया।

इसके बाद तालिबान ने सेना के कमांडरों, जिलों और प्रांत स्तर के नेताओं से संपर्क किया। उन्हें इस बात के लिए राजी किया की वो अगर सैनिकों से हथियार डलवा दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। इसके लिए सैनिकों और कमांडरों के कबीले, दोस्त, परिवार की मदद भी तालिबान ने ली। उनकी ये चाल कामयाब रही। तालिबान ने काबुल फतह के लिए प्रोपेगेंडा का भी सहारा लिया। उसने ये बात, डर और दहशत आम लोगों से लेकर सैनिकों तक के दिमाग में बिठा दी कि आखिर में जीतेगा तो तालिबान ही और इसलिए बिना वजह ना तो तालिबान का विरोध करें और ना ही तालिबान से दुश्मनी मोल लें। तालिबान का ये प्रोपेगेंडा काम कर गया और अफगानिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ।

भारत के ऑप्शंस

यह कोई संयोग भर नहीं है कि जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, उसी समय उसकी विदेश नीति पूर्वी एशिया पर केंद्रित हो रही है।

इस बात पर आम सहमति बढ़ती जा रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने विफल युद्धों में ही संलग्न बने रहने के बजाय अब चीन के साथ उभरती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिये स्वयं को तत्काल तैयार करना चाहिये।

तालिबान को पराजित करना और अफगानिस्तान का राष्ट्र-निर्माण अमेरिका की नव-रूढ़िवादी विचारधारा (लोकतंत्र को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप) का अंग रहा था, जो स्पष्ट रूप से विफल रहा है।

हालाँकि अमेरिका भले ही अफगान सरकार का साथ छोड़ दे और इससे बाहर निकल आए किंतु भारत यह जोखिम नहीं उठा सकता। उसे न केवल अपने निवेश की रक्षा करनी है बल्कि अफगानिस्तान को भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के लिये एक और सुरक्षित आश्रय बनने से रोकना है। इसके साथ ही भारत को काबुल के ऊपर पाकिस्तान के प्रभाव में वृद्धि पर भी संतुलित नियंत्रण कायम रखना है। अब जानकारों की माने तो अफगानिस्तान में जब तक अगली सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक भारत सरकार की ओर से कोई रुख नहीं अपनाया जाएगा। भारत 'वेट एंड वॉच' की स्थिति ही बनाए रहेगा। भारत सरकार के सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि अभी अफगानिस्तान में सरकार बनने का इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह की सरकार बनेगी, उसी आधार पर भारत आगे अपना रुख तय करेगा। मतलब भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए हुए है। भारत की नजर इस पर है कि अफगानिस्तान में अब पूर्ण तालिबानी सरकार बनेगी या अभी फिलहाल अंतरिम सरकार ही बनेगी। हालांकि तालिबान के प्रवक्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं कि अफगानिस्तान में भारत की ओर से जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसमें तालिबान किसी तरह की बाधा नहीं डालेगा।

अब इसमें तो कोई शक की गुंजाईश नहीं है की अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के परिणामों के प्रभाव भारत पर भी पडेंगे अत: उसे अपने हितों की रक्षा और अफगानिस्तान की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये यूरेशियाई शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना ही होगा।

ऑपरेशन देवी शक्ति

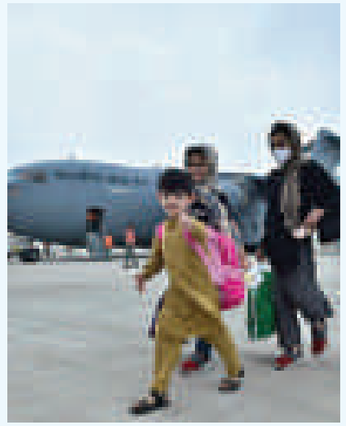

हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर चलाए गए राहत और बचाव अभियान को "ऑपरेशन देवी शक्ति" (Operation Devi Shakti) नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ऑपरेशन देवी शक्ति रखा है'। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि आखिर ये नाम कैसे अस्तित्व में आया। ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये नाम इसलिए चुना गया था क्योंकि निर्दोष नागरिकों को हिंसा से बचाने का ये एक प्रयास है, जैसे 'माँ दुर्गा' निर्दोषों को राक्षसों से बचाती हैं ठीक वैसे ही क़ाबुल से निर्दोष लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए भी ऐसे ही ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं और दोनों नवरात्रों में नौ दिनों का उपवास रखते हैं। नौ दिनों तक सिर्फ गर्म पानी पीते हैं और कभी-कभी एक समय एक फल ही भोजन में लेते हैं।

हाल ही में सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने केबिनेट को निर्देश दिया था कि अफगानिस्तान से आए लोगों के बचाव अभियान को मानवीय नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न केवल हिंदुओं और सिखों जैसे अल्पसंख्यकों को विभिन्न उड़ानों से अफगानिस्तान से वापस लाएं, बल्कि कई अफगान नागरिकों ने भी संकट की इस घड़ी में भारत आने का विकल्प चुनना पसंद किया है, इसलिए उन्हें भी भारत लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।

तालिबान से घिरे काबुल के ताजिक शहर से निकाले जाने के एक दिन बाद भारत मंगलवार को अपने 25 नागरिकों और दुशांबे से कई अफगान सिखों और हिंदुओं सहित 78 लोगों को वापस लाया। सिख धर्मग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब की तीन प्रतियों के साथ समूह को सोमवार को भारतीय वायु सेना के एक सैन्य परिवहन विमान द्वारा काबुल से दुशांबे ले जाया गया। इस मौक़े पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोगों का स्वागत भी किया।

निवेशकों का बढ़ा भरोसा

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 2.64 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बीते चार वर्षों में काफी तेजी से मजबूत हुई है। चाहे खेती–किसानी की बात करें या उद्योग धंधों की। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। वित्त वर्ष 2020–21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मामले में यह प्रदेश देश में पांचवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कोविड लॉकडाउन के बावजूद बीते वर्ष जीएसडीपी 19.48 लाख करोड़ रुपये दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक साल में तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक को पीछे छोड़ने के बाद अब यह सिर्फ महाराष्ट्र से पीछे रह गया है।

प्रदेश की इस तेज तरक्की के पीछे सरकार की निवेशक हित वाली नीतियां हैं। अलग–अलग सेक्टर के अनेक उद्योगपति राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टर समिट में हुए 4.68 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में से तीन लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। बीते दो वर्षों में उत्तर प्रदेश से निर्यात भी 32% बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार बड़े उद्योगपति इस पैमाने पर पैसा लगा रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और अच्छी नीतियां हैं। बदले वातावरण में भारतीय और विदेशी निवेशक टेक्सटाइल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल स्टेट पावर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरह निवेश कर रहे हैं, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था।

पिछले साल महामारी और लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के सामने दोहरी समस्या थी। एक तो मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर जैसे उत्पादों की मांग अचानक बढ़ गई और दूसरी तरफ लाखों प्रवासी मजदूरों को काम का प्रशिक्षण देने और उनके पुनर्वास की चुनौती थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एमएसएमई सेक्टर और स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने पर मदद करने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री कहते हैं, "महामारी के समय हमने चीनी मिलों और डिस्टलरी में सैनिटाइजर का उत्पादन किया था ताकि प्रदेश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश ने दूसरे राज्यों को सैनिटाइजर भेजे। महामारी से पहले हम चीन से पीपीई किट आयात करते थे। हमने स्थानीय निर्माताओं को किट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें दूसरे राज्यों को भी भेजा गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू की गई योजनाओं में अनेक लोगों को काम मिला। रोजगार पोर्टल के जरिए दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को एमएसएमई इकाइयों में रोजगार मुहैया कराया गया।"

कोविड काल में रोजगार सृजन के मामले में हाल ही उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य घोषित किया गया है। एमएसएमई इकाइयों ने उत्तर प्रदेश में अन्य किसी भी राज्य की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी) के मामले में भी प्रदेश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।

कोरोना लॉकडाउन के विपरीत प्रभावों से बचाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान उद्योगों को सब्सिडी और लोन दिया था। कोरोना के असर से पहले भी योगी आदित्यनाथ सरकार उद्योगों की पूंजी और कर्ज की जरूरतों को लेकर संवेदनशील रही है। चार साल के कार्यकाल में इस सरकार ने 55,45,147 एमएसएमई इकाइयों को कर्ज दिलाने के लिए बैंकों के साथ समन्वय स्थापित किया। इन इकाइयों ने 2.64 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है।

दुनिया की शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चीन से स्थानांतरित कर नोएडा में स्थापित किया है। इसके कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत में सैमसंग के दक्षिण पश्चिम एशिया प्रेसिडेंट और सीईओ केन कांग ने स्वयं यह जानकारी दी। यह न सिर्फ 'मेक इन इंडिया' की सफलता का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि यह बताता है कि विदेशी निवेशकों को प्रदेश सरकार के नेतृत्व पर कितना भरोसा है।

चार साल में साढ़े चार लाख से अधिक सरकारी नौकरी

योगी आदित्यनाथ सरकार के चार साल के कार्यकाल में साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं। इनमें से एक लाख से अधिक नौकरियां महिलाओं को दी गईं। लगभग 86,000 रिक्त जगहों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है। राज्य सरकार ने पांच लाख से अधिक युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने में भी मदद की। एक जिला एक प्रोजेक्ट की मदद से 25 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए गए। इनके अलावा करीब डेढ़ करोड़ लोगों को मनरेगा से जोड़ा गया।

प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी) के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यहां 136 करोड़ रुपये के निवेश से 4,143 इकाइयां स्थापित हुईं और 43,118 लोगों को काम मिला। सच तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों के चलते यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के 2,572 इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में 1,571 ज्यादा इकाइयां स्थापित हुईं। इन इकाइयों को आयोग के 77.16 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 59 करोड़ रुपये अधिक रकम उपलब्ध कराई गई।

बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लांच की गई। इसके तहत स्वरोजगार के लिए युवाओं को 25 लाख रुपये रुपये की मदद दी जाती है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लोगों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। अल्प अवधि के इस प्रशिक्षण का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। छोटी इकाइयां स्थापित करने के लिए 25% मार्जिन मनी भी दी जाती है।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को 10 लाख रुपये पूंजी की मदद की जाती है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना और वहां से पढ़े–लिखे युवाओं का शहरों में पलायन रोकना है।

कोविड संकट में भी गेहूं-धान की रिकॉर्ड खरीद

कोविड–19 की चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद की है। इस वर्ष 12.98 लाख किसानों से 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। यह खरीद अप्रैल में शुरू हुई थी और राज्य सरकार अभी तक किसानों को 11,141.28 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। पिछली सरकार ने 2016–17 में 7.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। उसकी तुलना में इस वर्ष आठ गुना खरीद हुई है।

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2017–18 के रबी विपणन वर्ष में 8,00,646 किसानों से 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। 2018–19 में 52.92 लाख मीट्रिक टन और 2019–20 में 37.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। 2020–21 में यह खरीद 35.76 लाख मीट्रिक टन रही। बीते चार वर्षों में गेहूं खरीद के बदले किसानों को 29,017.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई। 2020–21 में राज्य सरकार ने 66.83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और बदले में करीब 12 लाख किसानों को 12438.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 2019–20 में 7,06,549 किसानों से 56.57 मीट्रिक टन, 2018–19 में 6,84,013 किसानों से 48.25 लाख मीट्रिक टन और 2017–18 में 4,92,038 किसानों से 42.90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। धान खरीद के मामले में भी योगी आदित्यनाथ सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले काफी आगे रही। इस सरकार ने चार वर्षों में 31,88,529 किसानों को 37825.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया। पिछली सरकार ने पांच वर्षों में 14,87,519 किसानों को 17,190.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। यानी पिछली सरकार के पांच वर्षों में धान का जितना मूल्य किसानों को दिया गया, उसका दोगुने से भी ज्यादा भुगतान योगी जी की सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में ही कर दिया है।

छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने औषधीय पौधों की खेती की बड़ी योजना तैयार की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कम समय में ही किसानों की आमदनी काफी बढ़ जाएगी। बुंदेलखंड में पायलट प्रोजेक्ट के बाद राज्य सरकार ने पूर्वांचल के किसानों को इसका लाभ देने के प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य सरकार मेरठ, मथुरा और फिरोजाबाद जैसे जिलों में भी औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है।

एमएसएमई

लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को दी गति

बड़े उद्योगों की तुलना में एमएसएमई कम पूंजी में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इनकी एक बड़ी खासियत यह है कि इनसे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में औद्योगीकरण में मदद मिलती है। एंसिलरी यूनिट के तौर पर ये बड़े उद्योगों की बड़ी मदद भी करते हैं। करीब 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार एमएसएमई सेक्टर ने ही दिया है। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी इस सेक्टर ने सिर्फ अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाया, बल्कि लाखों

लोगों की नौकरियों को भी बरकरार रखा। योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल और नीतियों के चलते लाखों इकाइयों का रिवाइवल संभव हो सका।

सरकार की मदद से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों ने सराहनीय कार्य किया है पिछले वर्ष कोविड काल में करीब 34,000 एमएसएमई इकाइयों को आर्थिक सहायता दी गई। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित एमएसएमई को दोबारा खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,542 इकाइयों को 2,505.58 करोड़ रुपये का कर्ज दिया। यह कर्ज 23 जून को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम में दिया गया।

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेरोजगारी की समस्या से भलीभांति वाकिफ हैं। इसलिए उनकी सरकार औद्योगिक विकास की गति बढ़ाकर रोजगार के और मौके सृजित करना चाहती है। मुख्यमंत्री कहते हैं, "आज प्रदेश के युवा नौकरी ढूंढ़ने के बजाय नौकरी देने पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना से युवाओं को काफी मदद मिली है। महिलाओं ने स्वरोजगार की दिशा में काफी उत्साह दिखाया है।" सरकार ने अनेक इकाइयों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी भी दी है। पिछले वर्ष 45,166 लोगों को रोजगार देने वाली 4571 एमएसएमई इकाइयों को 140 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।

फूड प्रोसेसिंग

उत्तर प्रदेश देश में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बावजूद खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में 10% से भी कम फल और सब्जियों का प्रसंस्करण हो पाता है। हर साल बड़ी मात्रा में फल सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को पहचानते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 लेकर आई थी ताकि इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इस नीति के बाद खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों का रुझान बढ़ा है।

इस सेक्टर में कई बड़े उद्योग आकर्षित हुए हैं जो अपनी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। बीते चार वर्षों में राज्य सरकार को 9105.58 करोड़ रुपये निवेश के लिए 139 प्रस्ताव मिले। इनमें से 101 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में काम शुरू हो गया है। इन कंपनियों ने 20,176 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इनके अलावा 38 इकाइयां अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। इन पर 5031.31 करोड रुपये निवेश का अनुमान है। इनमें इस वर्ष के अंत तक उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल ने बड़ी संख्या में किसानों और छोटे उद्यमियों को भी आकर्षित किया है। इस पहल में छोटे व्यवसायियों को 10 लाख रुपये की लागत वाली इकाइयां स्थापित करने के लिए लोन पर 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस खास पहल के बाद बागवानी विभाग को मौजूदा छोटी इकाइयों के आधुनिकीकरण और नई इकाइयां स्थापित करने के अनेक आवेदन प्राप्त हुए। इन्हें जल्दी ही स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। सरकार ने इस वर्ष 9301 माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनसे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

योगी सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज अपग्रेडेशन स्कीम के तहत यह पहल की है। इससे एक तरफ किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिलती है तो दूसरी तरफ छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा मिलता है। सरकार नए उद्यमियों को आसान कर्ज भी सुनिश्चित कर रही है। यह योजना योगी सरकार की कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से राज्य का विकास तेज करने की मुहिम का हिस्सा है।

9301
माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित

20,000
लोगों को रोजगार

25
फीसदी, बंद चीनी मिलें दोबारा शुरू

किसान हितैषी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में किसान ऊंचे पायदान पर हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ किसान कल्याण में विश्वास करते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के उनके सच्चे प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य, कर्ज मुक्ति से किसान कल्याण तक है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश किसानों को भुगतान करने में अव्वल रहा है। कोरोना काल में भी योगी सरकार ने किसान कल्याण के इस महायज्ञ को रुकने नहीं दिया है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान हुआ। पिछले साल 19 जून 2020 तक गन्ना किसानों के खाते में 418 करोड़ रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी। प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाते हुए, मुख्यमंत्री ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया। यह सब संभव हो सका क्योंकि, किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद संभालने के बाद से ही किसान कल्याण के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। यही वजह है कि इसके नतीजे दिखाई दे रहे हैं।

2017–20 के बीच किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। यह भुगतान इससे पहले के तीन वर्षों के कुल गन्ना मूल्य भुगतान 53,367 करोड़ रुपये से 64,578 करोड़ रुपये ज्यादा है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में अव्वल बना है। उनके प्रयासों से ही 25 फीसदी, बंद चीनी मिलें दोबारा शुरू हो पाई हैं। ई–गन्ना एप के जरिये किसान तकनीकी तौर पर समृद्ध हुए।

- **गन्ना किसानों के खाते में 418 करोड़ रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर**
- **किसानों के लिए ई-गन्ना एप का अभिनव प्रयोग**
- **2017-20 के बीच किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया**

इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसपी खरीद पर जोर दिया। उनका लक्ष्य था कि हर किसान के एक–एक दाने का उचित मूल्य उसे अवश्य मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी कर रही है। सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। 2017–18 में यह 1625 रुपये, 2018–19 में 1735 रुपये और 2019–20 में 1840 रुपये था। समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है। सरकार ने उपज खरीद केंद्रों को भी बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि किसानों को उपज बेचने में आसानी हो और उन्हें ज्यादा दूरी न तय करनी पड़े। पिछले चार साल की खरीद में गेहूं किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29,017.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। भुगतान प्रक्रिया में भ्रष्टाचार रोकने के लिए योगी सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। सरकार का मानना है कि किसान खुशहाल रहेंगे, तो राज्य में खुशहाली रहेगी। किसानों के हित सर्वोपरि रखने के कारण भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है।

- **उपज खरीद के लिए सैकड़ों नए केंद्र खोले गए।**
- **पिछले चार साल में गेहूं किसानों को 29,017.45 करोड़ रुपये का भुगतान।**
- **किसानों को 66000 करोड़ रुपये का भुगतान कर 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद की गई।**
- **इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 66.83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो पिछले साल के मुकाबले डेढ़ गुना ज्यादा है।**
- **प्रदेश में 1.80 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।**

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.41 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 27,286 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई है। उत्तर प्रदेश इसमें अव्वल।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 5 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
- इसके अंतर्गत 21.64 लाख किसानों को 1910 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है।
- अब तक किसानों को 3 लाख 58 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया जा चुका है।
- योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का गठन किया है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत इस वर्ष 600 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है।
- 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- मंडी शुल्क में एक प्रतिशत की कटौती की गई है और 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडियों के रूप में विकसित किया गया है।
- अब तक 3911.71 लाख टन गन्ना पेराई कर 427.30 लाख टन से ज्यादा चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है।
- 45.44 लाख गन्ना किसानों को 1.26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है।
- गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रदेश को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान मिला है।
- 25 सालों में पहली बार नई खांडसारी इकाईयों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

टेक्सटाइल, लेदर

कानपुर को वापस मिलेगा खोया रुतबा

बीते चार वर्षों में उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर ने अनेक निवेशकों को आकर्षित किया है। भारतीय उद्योग जगत के कई बड़े नामों ने 8715.16 करोड़ रुपये के निवेश से 152 फैक्ट्रियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इनमें से 12 का काम पूरा हो चुका है और 18 में काम चल रहा है। इन 152 फैक्ट्रियों में 5,25,087 लोगों को रोजगार मिल सकता है। 18 फैक्ट्रियों में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद है। इनके अलावा 17 फैक्ट्रियों में कंस्ट्रक्शन का काम भी इसी साल शुरू हो जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से कानपुर शहर 'पूर्व का मैनचेस्टर' का रुतबा फिर से हासिल करने जा रहा है। अनेक बड़े उद्योगपति कानपुर शहर और उसके आसपास अपनी इकाइयां लगाने के लिए उत्सुक हैं।

कानपुर में एक मेगा लेदर पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। 235 एकड़ क्षेत्र में फैला यह पार्क मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 5,850 करोड़ रुपये का निवेश होगा। मेगा लेदर पार्क कानपुर शहर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। रमईपुर गांव में प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट से कानपुर एक बार फिर टेक्सटाइल हब और लेदर सिटी के तौर पर जाना जाएगा।

लेदर पार्क के अलावा राज्य सरकार को कानपुर शहर और कानपुर देहात इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए 23 प्रस्ताव मिले हैं। इन परियोजनाओं में करीब 4,000 करोड़ रुपये का निवेश होने और लगभग 7,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अभी तक जो 23 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, उनमें से 11 पर काम आगे बढ़ चुका है और इन औद्योगिक इकाइयों में जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाएगा।

जैव ऊर्जा नीति

सरकार कृषि आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नई जैव ऊर्जा नीति लाने वाली है। यह नीति किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन पैदा करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनाएगी। यह जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना का जरिया भी बनेगी। कृषि अपशिष्ट (पराली) पर भी यह नीति कारगर होगी। इससे खेतों में पराली का जलना बंद होगा, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग ने नई राज्य जैव ऊर्जा नीति का मसौदा तैयार किया है। जल्द ही नई राज्य जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2018 में जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए राज्य जैव उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम भी लागू कर चुके हैं। इसके अंतर्गत जैव ऊर्जा उद्यमों को पूंजीगत उपादान, राज्य जीएसटी से दस सालों तक पूरी तरह प्रतिपूर्ति और इन उद्यमों की स्थापना के लिए भूमि क्रय पर स्टाम्प डयूटी में पूर्ण रूप से छूट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी।

इस नीति में प्रदेश सरकार पर एकमुश्त खर्च के अलावा प्रति वर्ष करीब 257.40 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। इस नीति के चलते नगरीय ठोस अपशिष्ट, कृषि उपज मंडियों के अपशिष्ट, चीनी मिलों के अपशिष्ट का उपयोग होगा और पशुधन से जैव ऊर्जा उत्पन्न करने के विकल्प खुलेंगे। नीति में धान की पराली आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना, कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी), बायो कोल, बायो एथनॉल और बायो डीजल के उत्पादन और उपयोग की रणनीति भी शामिल है। नीति में कई तरह की छूट और प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी है।

अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार कौन?

रंजना मिश्रा

आज पूरी दुनिया अफगानिस्तान की तस्वीर देखकर हैरान है। अफगानियों की बेबसी बेचैन करने वाली है। उनके हालात देखकर तरस आ रहा है। लोगों के मन में बस यही प्रश्न है कि तालिबान आखिर इतनी आसानी से अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कैसे सफल हो गया? अफगानिस्तान में लोगों के जानवरों से भी बदतर इन हालातों के लिए लोग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को दोषी मान रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे इतिहास में अमेरिका की सबसे बड़ी हार कह रहे हैं व बाइडेन से इस्तीफा मांग रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वालेस ने भी कहा है कि अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला अमेरिका की एक गलती है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए पहले 11 सितंबर की तारीख तय थी फिर 31 अगस्त तय कर दी गई, लेकिन

तालिबानियों ने 15 अगस्त को ही काबुल पर कब्जा कर लिया।

अमेरिका से सेना वापस बुलाने की बात सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उन्होंने इसके लिए 1 मई 2021 की तारीख तय की थी, जिसे बढ़ाकर जो बाइडेन ने 31 अगस्त 2021 कर दी। इससे पहले अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में एक समझौता हुआ था, जिसे दोहा समझौता कहा जाता है, इसके अनुसार तालिबान अपने इलाके में अल कायदा और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। राष्ट्रीय स्तर पर शांति से बात होगी लेकिन तालिबान ने हमले शुरू कर दिए और फिर अमेरिकी सैनिक वापसी की तैयारी करने लगे। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने का मतलब, अफ़गानिस्तान तालिबान को सौंपना था? जाहिर है अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। 8 अगस्त को जो बाइडेन से पूछा गया था कि क्या तालिबान अफगानिस्तान पर जल्द ही कब्जा कर लेगा तब बाइडेन ने कहा था ऐसा नहीं होगा।

हालांकि अमेरिकी एजेंसी बाइडेन सरकार को बता रही थी कि तालिबान कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाइडेन सरकार ने इस पर न कोई ध्यान दिया और ना ही कोई एक्शन लिया और नतीजा आज दुनिया के सामने है। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के सहयोगी देशों ने पिछले 20 सालों में काफी समय अफगान सुरक्षाबलों को ट्रेनिंग देने में खर्च किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह सब हुआ जरूर, लेकिन सैनिकों को लेकर शुरू से ही अफगानिस्तान में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। अमेरिका जिस तरह से मौन है, उससे जाहिर है कि बाइडेन यह ठान चुके थे कि अफगानिस्तान की आग में अमेरिका अब अपने हाथ और नहीं जलाएगा। इसीलिए लोग बाइडेन को अफगानिस्तान के इस हाल के लिए दोषी करार दे रहे हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि अफगानिस्तान की सरकार भी इसके लिए बराबर की कसूरवार है। अफगानिस्तान की सरकार अब तक अमेरिका के सहारे फल-फूल रही थी। चिंता मुक्त, चुनौती मुक्त, तरक्की और ताकत जुटाने की जिम्मेदारी से मुक्त यह सरकार बिल्कुल सुस्त और दिशाहीन थी, यही वजह थी कि सरकार के नुमाइंदे करप्शन के अथाह समुद्र में डूबते गए। नेता और बड़े अफसर देश के सिस्टम को खोखला करते रहे, ये खोखली सरकार और सिस्टम सिर्फ 75 हजार आतंकियों के आगे धराशायी हो गए। लोगों के मन में सवाल है कि अफगानिस्तान के सैनिक आखिर क्या कर रहे थे? वायुसेना होने के बावजूद जमीन पर मुट्ठी भर लोग कैसे जीतते रहे और आगे बढ़ते रहे? सच तो यह है कि तालिबान मजबूत नहीं, बल्कि अशरफ गनी बहुत कमजोर थे।

तालिबान एक आतंकी ग्रुप है। कट्टर सोच, लड़ने-मरने का जज्बा और आंख बंद कर अपने अफसरों की बात मान लेना तालिबानी लड़ाकों की खासियत है। दूसरी ओर अशरफ गनी का न अपने गवर्नर्स पर कंट्रोल था और ना ही नेताओं पर। ना अशरफ गनी ने अपनी सेना और पुलिस को मजबूत करने पर कभी ध्यान दिया। तालिबान ने अपने मिशन की शुरुआत छोटे प्रांतों से की, तालिबानियों ने अफगानिस्तानी नेताओं को मिलाया, सैनिकों के परिवार वालों और परिचितों से संपर्क किया। तालिबान के ब्रेनवाश से नेता व सैनिक सरेंडर करते रहे। हर देश की तरह अफगानिस्तान भी अपनी सुरक्षा के लिए एक मोटा फंड रिलीज करता था लेकिन करप्शन के चलते सेना के जवानों को घटिया खाना व घटिया हथियार मिल रहे थे, उन्हें जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। सेना के लिए जो हथियार और गोला-बारूद खरीदे गए, उनकी भी कालाबाजारी होती थी, यही वजह है कि तालिबानियों के हाथों में इतने आधुनिक हथियार नजर आते हैं। अफगानिस्तान के अफसर व नेता हथियार बेचकर दौलत बटोर रहे थे तो वहीं तालिबान का हथियार डिपो दिन-रात बढ़ता जा रहा था। अमेरिका के रहते तालिबान खामोश जरूर था लेकिन सक्रिय भी था।

तालिबान पहले पश्तूनों का ग्रुप माना जाता था, बाद में यह उत्तरी इलाके में भी फैल गया। तालिबानी गांव-गांव में अपने समर्थक बनाते रहे। तालिबान फैलता रहा और अमेरिकी एजेंसियां सोती रहीं। इससे पता चलता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां या तो नाकाम रहीं या वो इतनी बेफिक्र थीं कि तालिबान के फैलने की रिपोर्ट ही न दे सकीं। अशरफ गनी की हालत से उनकी सेना के अफसर और सैनिक अच्छी तरह परिचित थे, इसीलिए हर महीने करीब 5000 सैनिक नौकरी छोड़ रहे थे। यह स्थिति किसी भी देश के लिए बेहद खतरनाक होती है, लेकिन अशरफ गनी और उनके सहयोगियों ने इसे रोकने या नई भर्ती पर कोई ध्यान नहीं दिया। तालिबान ने चंद दिनों में साबित कर दिया था कि उसकी जीत तय है, लेकिन लोगों को सेना और वायु सेना पर भरोसा था, अशरफ गनी को अमेरिका पर भरोसा था, लेकिन जिन्हें फ्रंट पर जाकर लोगों की जान बचानी थी, सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान के सैनिकों को पता था कि उनकी जान की परवाह सरकार को रत्ती भर भी नहीं है।

अफसर, नेताओं और रणनीतिकारों के मुंह में काली कमाई का खून लग चुका था। जिसे सिर्फ अपने फायदे की सोचने की लत लग जाए, वो इन अफगानियों के बारे में क्या सोचता? यही वजह है कि आज अफगानिस्तान के लोग सताए जा रहे हैं, रो रहे हैं, सड़कों पर बेमौत मारे जा रहे हैं और प्लेन से गिरकर जान गंवा रहे हैं, उनका अपना ही मुल्क जहन्नुम बन गया है।स्स्स्क

नया तालिबान यानी कश्मीर के संदर्भ में नई चुनौती

नवीन जैन

लगातार बढ़ती जा रही तकनीकी के चलते आज कोई स्कूल के छात्र से लेकर बुजुर्गवार की बेचैनी यह जानने की है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो कुछ कर रहा है, उसके असर भारत पर कितने ओर कैसे होंगे। तमाम गुना भाग का गुणनफल यह भी निकल सकता है कि तालिबान यदि अफगानिस्तान पर वाकई काबिज़ हो गया, तो भारत के लिए यह अशुभ संकेत ही होगा। खासकर जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में। सनद रहे कि जब बराक ओबामा जब 2014 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अमेरिका शीघ्र अफगानिस्तान से अपनी पूरी सेना वापस बुला लेगा। बराक ओबामा की उक्त घोषणा जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनीं, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना अजहर मसूद ने ताबड़तोड़ अपने तेवर दिखा दिए। सईद ने कहा कि जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी कुमुक लौटेगी, वैसे ही हमारा संगठन कश्मीर घाटी से भारतीय सैनिकों को खदेड़ देगा। वो तो अच्छा हुआ कि 2014 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार केन्द्र में बहुमत से आ गई। तब जम्मू कश्मीर का मसला भी उसके एजेंडा में था। तकनीकी कारणों से जब दुबारा मोदी सरकार भारी बहुमत से सत्ता में लौटी, तो संविधान से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटा दिए गए।

सनद रहे कि मोदी के कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर एअर सर्जिकल स्ट्राइक सफल रूप से हुई, जिनमें पाकिस्तानी इलाकों में आतंकी प्रशिक्षण अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। उस वक्त की ख़बरों के अनुसार भारत ने भले ही अपने सैनिक अफगानिस्तान की मदद के लिए कभी नहीं भेजे हों, लेकिन हथियारों की सप्लाई, और प्रशिक्षण के स्तर पर तालिबान के विरूद्ध पूरी मदद की गई। मुंबई के गेट वे हाउस नामक थिंक टेंक में कार्यरत समीर पाटील का कहना है कि जैसे-जैसे तालिबान की ताकत का अफगानिस्तान में विस्तार होगा, वैसे–वैसे पाकिस्तान मजबूत होता जाएगा। खबरें बहुत पहले आ चुकी हैं कि जब से तालिबान ने तीसरी बार अफगानिस्तान में सिर उठाया है तभी इमरान खान ने तालिबान लड़ाकों की मदद के लिए अपने 40 हज़ार सैनिकों को भेज दिया था। सनद रहे कि 9/11 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मुख्य आरोपी ओसमा बिन लादेन को पाकिस्तान ने ही छिपा कर रखा था। बाद में जब बराक ओबामा ने सरकार संभाली, तब अमेरिकी विमानों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर की गुफाओं में पनाह लिए बैठे ओसमा बिन लादेन को न सिर्फ घुसकर मार गिराया था, बल्कि उसके शव को अंतिम संस्कार के तहत प्रशांत महासागर में डुबो दिया था। इस पूरी एक्सरसाइज का पता पाकिस्तान को कानों कान नहीं चल पाया था, लेकिन पाकिस्तान की आज भी इतनी हैसियत कहाँ है कि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के राष्ट्रपति जो. बाइडेन से आँख से आँख मिलाकर बात कर सके।

सनद रहे कि मोदी के कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एअर सर्जिकल स्ट्राइक सफल रूप से हुई, जिनमें पाकिस्तानी इलाकों में आतंकी प्रशिक्षण अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। उस वक्त की ख़बरों के अनुसार भारत ने भले ही अपने सैनिक अफगानिस्तान की मदद के लिए कभी नहीं भेजे हों, लेकिन हथियारों की सप्लाई, और प्रशिक्षण के स्तर पर तालिबान के विरूद्ध पूरी मदद की गई।

जैसे ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अकूत अमेरिकी डॉलर लेकर देश छोड़ा है, इमरान खान ने तालिबान की खुलकर तारीफ शुरू कर दी है। इमरान ने कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, लेकिन जो ज़ेहनी गुलामी है उसकी ज़ंजीरें यूँ ही नहीं टूटती। इस बयान को भारत को चिढ़ाने वाला माना जा रहा है। समीर पाटील का कहना है कि इस बार अफगानिस्तान की वायु सेना कमज़ोर थी ओर, इसलिए भारत उसकी भरपूर मदद भी नही कर पाया। समीर पाटील कहते हैं कि अफगानिस्तान की फौज को कामयाबी इसलिए भी नहीं मिल पाई कि उसके 11000 स्पेशल फोर्स के जवानों को समय पर अति आधुनिक प्रशिक्षण भारत की ओर से नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी मारक शक्ति में वृद्धि नहीं हो पाई। समीर पाटील यह थ्योरी भी बताते हैं कि भारत रूस, ईरान के साथ मिलकर तालिबान विरोधी नीति बनाते तो कोई बात बनती, लेकिन इस बीच रूस, और इरान ने तालिबान के साथ शान्ति वार्ता शुरू कर दी। ऐसे में भारत के पास अकेले करने को क्या था।

समीर पाटील एक और अहम मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं। वे याद दिलाते हैं कि 1996 से 2001 के बीच मुल्ला उमर तालिबान के सर्वमान्य नेता थे। उस वक्त पाकिस्तान समेत चार देशों ने तालिबान को मान्यता दे रखी थी। समीर पाटील के अनुसार तालिबान के उदारवादी नेताओं का तब मानना था कि जब तक उनके देश में मूलभूत सुविधाओं का ढांचागत सुधार नहीं होता, तब तक समस्या इसी तरह उलझी रहेगी। इसके लिए ज़रूरी था कि अन्य देश भी तालिबान से हाथ मिला लेते, लेकिन इस तरह के नेक कामों में जितनी रुकावटें आएं, कम हैं। अन्य जानकारों का कहना है कि भारत ने, तो अफगानिस्तान में तीन अरब डॉलर का निवेश अब तक किया है, जिसमें वहाँ के संसद भवन का निर्माण, सडकों, पुलों, अस्पतालों

आदि का आधारभूत ढांचा तैयार करवाना भी शामिल है। इसके लिए अफगानिस्तान को अन्य देशों से भी मदद की दरकार थी। अब इसका क्या करें कि इस तरह की इमदाद पाकिस्तान, और चीन बढ़ चढ़कर कर सकता है लेकिन उसके इरादे गलत होते है। अब तालिबान की मजबूती में ही उक्त दोनों देशों को भारत की कमज़ोरी दिखाई दे रही है। चीन ने तो भारत की देखा-देखी वहाँ एक लंबी सड़क का निमार्ण भी शुरू कर दिया है।

जान लें कि तालिबान का अर्थ होता है छात्र यानी वो छात्र जो सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथ को मदरसों में पढ़े। अफगानिस्तान यदि तालिबान से हारा है, तो माना जा रहा है कि इस हार में भारत की भी भले पराजय न छिपी हो, लेकिन एक सावधानी या सीख, तो दबी पड़ी हुई है। एशिया में भारत लगातार अकेला पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान, और चीन, तो हमारे जानी दुश्मन हैं ही सही, अब मज़र ऐसा है कि नेपाल जैसा देश, जो भारत से नमक तक मंगाया करता था, वह भी जब तब आँखें तरेरने लगता है। भूटान, हो या श्रीलंका या बांग्लादेश या म्यामांर सभी कभी

समीर पाटील एक और अहम मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं। वे याद दिलाते हैं कि 1996 से 2001 के बीच मुल्ला उमर तालिबान के सर्वमान्य नेता थे। उस वक्त पाकिस्तान समेत चार देशों ने तालिबान को मान्यता दे रखी थी। समीर पाटील के अनुसार तालिबान के उदारवादी नेताओं का तब मानना था कि जब तक उनके देश में मूलभूत सुविधाओं का ढांचागत सुधार नहीं होता, तब तक समस्या इसी तरह उलझी रहेगी।

अपने थे, लेकिन आज पराए हो गए हैं। हाल के वर्षों में राजनय और जासूसी जैसी अनिवार्य बुराइयों के पसे मज़र यह भारत की चौकाने वाली हार तक कही जा रही है। भारत के लिए बस एक ही सम्भावना बताई जा रही है, ताकि अफगानिस्तान तालिबान के रूप में पाषाण या मध्यकालीन युग में जाने से बचे।

सबसे सफल हो सकने वाली थ्योरी यह बताई जा रही है कि अफगानिस्तान की उत्तरी पर्वतमालाओं में कभी अफगान मुजाहिदिनों ने तत्कालीन सोवियत संघ की नाक में दम कर रखा था। इन मुजाहिदीनों के कबीले जब एक जुट हुए, तो उनका नामकरण हुआ नार्दन अलॉयन्स। यह एक सैन्य संगठन है। कभी इसके कमाण्डर अहमद शाह ने भारत से घरोपा कर रखा था। इस बीच अल कायदा के एक बहुरुपिए फिदायीन ने न्यूज रिपोर्टर बनकर अहमद शाह की हत्या कर दी। अब अहमद शाह का बेटा अहमद मसूद नार्थन अलॉयन्स का कमांडर बना दिया गया है, जो फिलहाल लंदन में पढ़ रहा है। वह फ्रेंच भाषा का भी जानकार है। उसका कहना है कि चूँकि अमेरिकी सेना लौट रही है, इसलिए हम अपने मुजाहिदीनों को फिर एक जुट करके तालिबान से अफगान पुरुषों, स्त्रियों, और बच्चों के हितों के जंग के लिए उतरेंगे। अहमद मसूद ने इशारों इशारों में भारत के हक़ में भी बात कह दी है, और वह यह कि हमें अल कायदा का पूरी तरह नेस्तनाबूद करना है। ■■■

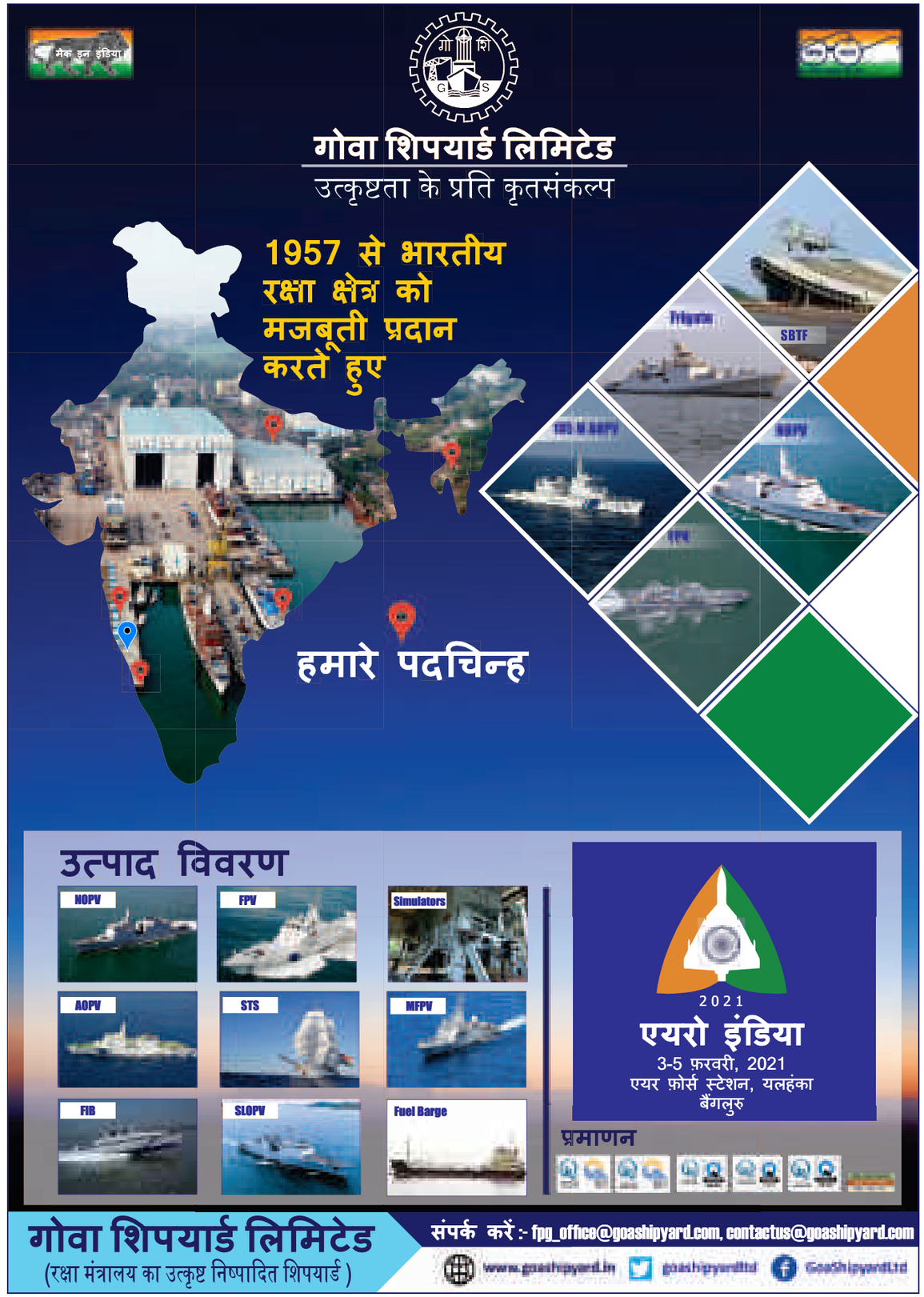

मनुष्य के लिए घातक
उदारता पर कट्टरता की जीत

सुयश मिश्रा

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अनुशासन का नियंत्रण सतही स्तर पर दो परस्पर विरोधी विषय लगते हैं किंतु जीवन में इन दोनों का ही बराबर महत्व है और व्यक्ति तथा समाज की सुख-शांति के लिए दोनों में समन्वय की आवश्यकता सदा अनुभव की जाती रही है। समाज के लिए व्यक्ति का होना अनिवार्य है। व्यक्ति ही नहीं होगा तो समाज बनेगा कैसे? और व्यक्ति के लिए समाज का अस्तित्व में रहना अपरिहार्य है क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उसकी निजी सुख-शांति समाज के मध्य ही संभव है। बिंदु के बिना सिंधु का होना और सिंधु के अभाव में बिंदु का अस्तित्व सुरक्षित रहना असंभव है। अफगानिस्तान में तालिबान सामाजिक अनुशासन के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करता हुआ बिंदु और सिंधु में संघर्ष उत्पन्न कर वहाँ का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रहा है जिसका दुष्प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। अत: तालिबानी शक्तियों के कृत्यों का औचित्य विचारणीय है।

लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देती हुई सामाजिक ताना-बाना बुनती है जबकि किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा शस्त्र-शक्ति के बल पर सत्ता पर अधिकार कर अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं और रूढ़ियों के माध्यम से समाज पर नियंत्रण करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करना है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है इसीलिए ऐसी अधिरोपित व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करता है। अफगानिस्तान में तालिबान और लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच की टकराहट व्यक्ति और समाज जनतंत्र और तानाशाही के मध्य जारी ऐसा ही संघर्ष है। इस संघर्ष में इस समय कट्टरता, उन्माद और नकारात्मक सोच को बढ़त मिली है जो उदारता, सामूहिकता और सह-अस्तित्व की पुष्टि के लिए शुभ नहीं कही जा सकती।

शासन की कोई भी प्रणाली कभी भी पूर्णतया निर्दोष नहीं होती। वह मनुष्य अथवा समान विचार वाले कुछ मनुष्यों द्वारा स्थापित की जाती है। मनुष्य पूर्ण होता नहीं इसलिए उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था में भी अपूर्णता रह जाती है। तथापि मनुष्य स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन का प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न प्राय: रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ किए जाते हैं तो इनके परिणाम भी अधिकांशत: शुभ होते हैं किंतु जब इन परिवर्तनकारी प्रयत्नों की दिशा पूर्वाग्रहों-दुराग्रहों, वैयक्तिक अथवा संकीर्ण सामूहिक स्वार्थों से प्रेरित होती है तब इनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। दुर्भाग्य से अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा शस्त्रबल के सहारे लाया गया वर्तमान परिवर्तन भी ऐसा ही प्रयत्न है क्योंकि उसका लक्ष्य वर्तमान समाज पर मध्यकालीन जीवन को आरोपित करना और समस्त विश्व-समुदाय को उसकी बहुरंगी छवियों से दूर कर एक रंग में रंगना है, विश्व का इस्लामीकरण करना है।

नदी के प्रवाह की भाँति मनुष्य का जीवन भी गतिशील है, परिवर्तनशील है। समाज के पटल पर समय पर प्रतिभाशाली विचारक जन्म लेते रहते हैं और अपने चिंतन से सामाजिक जीवन में देश-काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन का शंखनाद करते हैं। यह सामाजिक जीवन के विकास की सहज प्रक्रिया है किंतु जब कोई समूह देश में वर्तमान युगजीवन की आवश्यकता और अपेक्षाओं की अनदेखी करके धर्म के नाम पर लगभग चौदह सौ वर्ष पुरानी मान्यताओं को समाज पर बलपूर्वक थोपने पर अड़ जाए और उस जैसी विचारधारा वाले अन्य देशों का समर्थन भी उसे मिलने लगे तो यह स्थिति न केवल उस देश के निवासियों के लिए अपितु अन्य देशों के लिए भी खतरनाक हो जाती है। जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते हुए अन्य धर्मों के लोगों को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने को व्याकुल इन समूहों की बढ़ती ताकत विश्वशांति के लिए बढ़ता हुआ खतरा है। अन्य देशों में भी ऐसे समूह सक्रिय हैं और अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। भविष्य में अधिक शक्तिमान होने पर यह उनकी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को निगल जाएंगे। इसलिए समय रहते सावधान होना और ऐसी शक्तियों पर कठोर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।

तथाकथित धार्मिक समूहों, पंथों, संप्रदायों में बँटे सामाजिक समूहों में अनेक ऐसी कुरीतियां प्रचलित रही है जो समय के साथ आती रहीं और समाप्त होती गयीं। हिंदूसमाज में सतीप्रथा, देवदासी प्रथा, छुआछूत आदि कितनी ही अमानवीय बुराइयां रहीं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इनकी स्वीकृति भी मिलती है किंतु आज इनका निर्वाह करने का कोई दुराग्रह कहीं दिखाई नहीं देता। समाज अपने पुराने केंचुल को त्याग कर समरसता की दिशा में अग्रसर है। आज यदि हिंदुओं में से कोई समूह कहे कि उसे हिंदू धर्म में सतीप्रथा,

शासन की कोई भी प्रणाली कभी भी पूर्णतया निर्दोष नहीं होती। वह मनुष्य अथवा समान विचार वाले कुछ मनुष्यों द्वारा स्थापित की जाती है। मनुष्य पूर्ण होता नहीं इसलिए उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था में भी अपूर्णता रह जाती है। तथापि मनुष्य स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन का प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ किए जाते हैं तो इनके परिणाम भी अधिकांशतः शुभ होते हैं।

छुआछूत जैसी पुरानी रूढ़ियों को फिर से स्थापित करना है तो उसके इस दुराग्रह का कौन समर्थन करेगा? जो बुराई जब थी तब थी। यह विचार का विषय नहीं इतिहास का दुखद स्वप्न है जिसे विस्मृत करने में ही समाज की भलाई है। आज क्या होना चाहिए यह विचारणीय है। इसी दृष्टि से भारत एवं अन्य देशों में नई-नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मान्य हुई हैं किंतु आश्चर्य का विषय है कि कट्टर इस्लामिक विचारक आज भी अपने प्रभाव क्षेत्र में नई व्यवस्थाओं का स्वागत करने और जीर्ण-शीर्ण रूढ़ियों को तोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। सहअस्तित्व और बंधुत्व के उदार विचारों से समृद्ध इस्लामिक विचारकों को समर्थन देकर कट्टरता और हिंसक उन्माद का पोषण करने वाली आतंकवाद की पैर पसारती मानसिकता को रोकना ही होगा अन्यथा तालिबानी ताकतें न केवल अफगानिस्तान में अपितु समस्त विश्व में यूं ही रक्तपात करती रहेंगी। विचारणीय यह भी है कि जब अन्य धर्मों के लोग अपनी रूढ़ियों और कुरीतियों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो इस्लाम के कट्टरपंथी तथाकथित बुद्धिजीवी अपने समाज को रूढ़ि मुक्त वातावरण देने के विरुद्ध क्यों अड़े हैं और समाज उनका खुलकर विरोध क्यों नहीं करता? वह उनका मौन समर्थन क्यों करता है? जब तक मुस्लिम समाज के अंदर से रूढ़ि-विरोधी स्वर मुखर नहीं होंगे तब तक तालिबानी जिहादी मानसिकता का समाप्त होना कठिन है।

धर्म ईश्वरीय अस्तित्व की स्वीकृति है और मानवीय-मूल्यों की आधार भूमि है। विभिन्न धर्मों की पूजा-पद्धतियां भिन्न हैं, साधना-पथ भिन्न हैं किंतु लक्ष्य एक है ईश्वर की कृपा प्राप्ति। हिंदूभक्त ईश्वर का अनुग्रह चाहता है, मुसलमान अल्लाह का करम पाने के लिए पांच बार नमाज अता करता है, ईसाई प्रेयर और सिख अरदास करता है। सब उस अदृश्य की कृपा पाने को प्रयत्नशील हैं फिर विरोध क्यों? जब सारी सृष्टि उस एक शक्ति की ही रचना है फिर संघर्ष क्यों? वस्तुत: संघर्ष धर्म का नहीं, सत्ता का है सुविधा का है। सत्ता और सुविधा के लिए समूह के विस्तार का है। इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबानी मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून बहा रहा है। अफगानिस्तान को अशांत कर रहा है और विश्व के अन्य देशों को अशांत करने के लिए आतुर है। इसीलिए विश्व समुदाय तालिबानियों की जीत पर चिंतित है। उदारता पर कट्टरता की जीत मनुष्य के लिए घातक है। पीड़ित अफगानियों के लिए विश्व की शक्ति का आगे आना अत्यंत आवश्यक है।

बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच

क्या होगा परिणाम?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा शुरू हुई, वह अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि इस जांच का नतीजा जल्द ही दिखने लगेगा। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कोलकाता से संजय सिन्हाः

पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। इसका परिणाम क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहले हिंसा मामलों की जांच के लिए 64 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अब, इस संख्या को बढ़ाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने टीम में 109 अधिकारियों को शामिल किया है। इन्हें 'स्पेशल 109' भी कहा जा रहा है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सीबीआई लगातार हिंसा के मामलों की जांच में जुटी है। हिंसा की जांच के लिए बनाई गई टीम के 84 जांच अधिकारियों में आईओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। 25 अधिकारी संयुक्त निदेशक, डीआईजी, एसपी रैंक के हैं।

हिंसा की जांच के लिए राज्य को चार जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन टीम में 21 जांच अधिकारी या आईओ रखे गए हैं। इसके पहले चार संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी पहुंच चुके हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हिंसा से जुड़े मामलों की जानकारी सीबीआई कार्यालय में आ रही है। सभी जिलों के एसपी हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट सीबीआई को भेज रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद संवैधानिक पीठ की देखरेख में सीबीआई हत्या, रेप और दुष्कर्म की कोशिशों से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। इसके लिए 109 लोगों की टीम का सीबीआई ने गठन किया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट

बताते चलें कि कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आदेश के बाद सीबीआई ने हिंसा की जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में सीबीआई टीम अभिजीत सरकार के परिवार वालों से पूछताछ भी कर चुकी है, जिनकी हत्या कथित तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कर दी थी।

हिंसा के मामले पर टीएमसी और बीजेपी भी आमने-सामने हैं। सीएम ममता बनर्जी हिंसा के आरोपों को खारिज कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 180 बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हत्या की है। स्पेशल क्राइम ब्रांच का अतिरिक्त प्रभार सीबीआइ में तैनात आईपीएस अखिलेश सिंह को दिया गया है जो कोयला और गो तस्करी की जांच का जिम्मा संभालते रहे हैं। उन्हें स्पेशल क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि इन अधिकारियों की टीम प्रत्येक जिले का दौरा करेगी और चुनाव बाद हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात कर आरोपितों की सूची तैयार करेगी। सीबीआइ ने कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग की होमीसाइड शाखा के अधिकारियों को तलब किया है। दरअसल कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार की होमीसाइड शाखा विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के दिन कोलकाता में हुई भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले की जांच कर रही है। चंद दिनों पहले सीबीआई जांचकर्ताओं ने मृत भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के कांकुरगाछी स्थित घर का दौरा किया था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारियों को बुलाया गया था। हाल ही में तीन पुलिस अधिकारी दस्तावेज लेकर निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सूत्रों के जो केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने होमीसाइड शाखा के अधिकारियों से अभिजीत सरकार की हत्या की जांच की प्रगति के बारे में बात की। आपको बता दें कि सीबीआई जांच में तेजी आती जा रही है। कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा।

अभिजीत सरकार के गमजदा परिवारवाले

भिक्षावृत्ति उन्मूलन व पुनर्वास की जरूरत

भारत के अधिकांश राज्यों में भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित कर दिया गया है। जेल और जुर्माना भी निर्धारित है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में भीख मांगना दंडनीय अपराध माना गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं स्थानों पर हजारों की संख्या में भिखारी सड़कों, स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों, मोहल्लों, कॉलोनियों आदि में आसानी से भीख मांगते देखे जा सकते हैं। ऐसे कई कारण हैं जो देश में भिक्षावृत्ति को जन्म देते हैं। गरीबी और बेरोजगारी एक ऐसा आर्थिक कारक है जो भीख मांगने को बढ़ावा देता है।

देवेन्द्रराज सुथार

हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक मानवीय और सराहनीय फैसला दिया है। कोरोना संक्रमण के नाम पर भिखारियों को सड़कों से हटाने के लिए दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भिखारियों और बेघरों को सड़कों से हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा अभिजात्य आदेश नहीं दे सकते। लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं। यह स्थिति शिक्षा और रोजगार में अवसरों की कमी से पैदा होती है। सवाल यह उठता है कि इंसान भीख मांगने की बजाए कुछ काम क्यों नहीं करता। इसका सीधा सा जवाब यह है कि वह भीख मांगने को ही काम मानता है।

दरअसल, भारत के अधिकांश राज्यों में भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित कर दिया गया है। जेल और जुर्माना भी निर्धारित है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में भीख मांगना दंडनीय अपराध माना गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं स्थानों पर हजारों की संख्या में भिखारी सड़कों, स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों, मोहल्लों, कॉलोनियों आदि में आसानी से भीख मांगते देखे जा सकते हैं। ऐसे कई कारण हैं जो देश में भिक्षावृत्ति को जन्म देते हैं। गरीबी और बेरोजगारी एक ऐसा आर्थिक कारक है जो भीख मांगने को बढ़ावा देता है। अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहिजों तथा रोगियों के कल्याण के लिए देश में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अत: वे भीख मांगने को मजबूर हैं। अन्य सामाजिक कारण भी भिक्षावृत्ति को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, निचली जातियों की विधवाएं या परित्यक्त महिलाएं भीख मांगती हैं। इसके अलावा कई मानसिक रोगी या गंभीर मानसिक संघर्ष से पीड़ित लोग आवारा बन जाते हैं और भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। बाढ़, भूकंप या अकाल आदि आपदाओं के कारण हजारों लोग बेघर और असहाय हो जाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने लगते हैं। अनाथ बच्चे और कमाने वाले की मौत भी कभी-कभी घर की महिलाओं और बच्चों को भिखारी बना देती हैं।

गौरतलब है कि 2018 में सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि देश में कुल 4,13,670 भिखारी हैं। जिनमें से 2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में हैं। यहां भिखारियों की संख्या 81,000 है। केंद्र शासित प्रदेशों में भिखारियों की संख्या सबसे कम है। लक्षद्वीप में 2, दादरा और नगर हवेली में 19, दमन और दीव में 22 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 56 भिखारी हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 2,187 और चंडीगढ़ में 121 भिखारी हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां भिखारियों की संख्या 65,835 है, जबकि आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है, यहां 30,218 भिखारी हैं। बिहार की बात करें तो यहां 29,723 भिखारी हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम में सबसे ज्यादा 22,116 और मिजोरम में सबसे कम 53 भिखारी है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में सालाना लगभग 215 करोड़ रुपये का भिक्षावृत्ति का कारोबार है। पूरे देश में पिछले लगभग 60 वर्षों से भिक्षावृत्ति निरोधक कानून चला आ रहा है, लेकिन भीख मांगने पर रोक लगाने में इस कानून को कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस कानून को लाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि भिक्षावृत्ति को एक व्यवस्थित व्यवसाय न बनने दिया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक आदि कारकों ने मिलकर इस समस्या को बहुत गंभीर बना दिया।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है, जिनमें से 50 प्रतिशत का पुलिस पता ही नहीं लगा पाती है। इनमें से अधिकांश बच्चों को संगठित अपराध में लिप्त संगठनों द्वारा पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति, मानव अंगों के अवैध व्यापार समेत भिक्षावृत्ति में धकेल दिया जाता है। भिक्षावृत्ति से जुड़े नाबालिगों का प्रयोग संगठित अपराध समूह कई अवैध गतिविधियों में करते हैं। उदाहरण के लिए ड्रग पेडलर, अवैध हथियारों की आवाजाही, पुलिस या अन्य की निगरानी, चोरी समेत अन्य छोटे-मोटे अपराधों इत्यादि में। इसके साथ ही कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि हत्या, लूट जैसे गंभीर मामलों में भी भिक्षावृत्ति में शामिल नाबालिगों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नाबालिगों के लिए कानून सख्त नहीं होते हैं और पकड़े जाने के बावजूद वह आसानी से कुछ समय बाद मामूली सजा काट कर वापस लौट आते हैं। इसके साथ ही भिक्षावृत्ति से जुड़े इन लोगों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है जो कि गंभीर चिंता का विषय है।

भिक्षावृत्ति की पृष्ठभूमि में बेरोजगारी और निर्धनता की अहम भूमिका है। इसलिए देश में उत्पादन के साधनों को बढ़ाना होगा। योजनाओं के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि हर कुशल और अकुशल श्रमिक को नौकरी मिल सके। शहरों और महानगरों में गुप्त तरीके से काम करने वाली कई ऐसी संस्थाएं हैं, जो बच्चों को पकड़कर, पीटकर, धमकाकर या अपंग बनाकर बेवजह भीख मंगवाती हैं। ऐसे संगठनों का पता लगाया जाना चाहिए और ऐसे संगठन चलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति या परिवार बाढ़, सूखा, पाला या किसी अन्य कारण से आर्थिक पतन के कगार पर पहुंच गया है, उसे बहाल करने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी कि भिखारियों के बच्चे भीख न मांगें। इसके लिए उनके बच्चों को शिक्षा देनी होगी। समाज में अधिक से अधिक अनाथालय एवं शरणालयों की स्थापना की जाए, जहां विकलांगों का इलाज हो और अनाथ बच्चों को सार्थक एवं कुछाल नागरिक बनाया जाए। ऐसा जनमत तैयार करना होगा कि अंधविश्वास के कारण और पुण्य परोपकार भावना के वशीभूत होकर व्यक्ति को दान के रूप में भिक्षा नहीं दे। इससे समाज में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

जो लोग शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित हैं और मजबूरी में भिखारी बन जाते हैं, उनका उचित इलाज होना चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास विकसित हो सके और वे भीख मांगने के जघन्य कृत्य में शामिल न हो सकें। अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं और गरीब परिवारों पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें विभिन्न कुटीर उद्योगों में उनकी उम्र के अनुसार प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए हमें पहले पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी होगी जिसमें हर व्यक्ति को नौकरी मिल सके या जीविकोपार्जन के ऐसे साधन उपलब्ध कराने होंगे ताकि लोग आसानी से जीवन निर्वाह कर सकें। कहा जाता है कि समस्या के कारण में ही समाधान होता है। आमतौर पर जिन कारणों से भीख मांगने को बढ़ावा दिया जाता है, अगर उन कारणों को दूर कर लिया जाए तो भीख मांगने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। अब समय आ गया है जब हमें जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कुछ योजनाओं के माध्यम से भीख मांगने वाले बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। इसमें पालनहार योजना, निराश्रित बाल गृह, शिशु गृह योजना और पालन गृह योजना आदि शामिल हैं। ऐसी योजनाओं को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने की दरकार है।

■■■

गीत गाया पत्थरों ने

रामप्पा ने राजा के भावों को बेजान पत्थरों पर उकेर कर उन्हें 40 सालों की मेहनत से उसे एक सुमधुर गीत जो बना दिया था। जी हां, रामप्पा ने 40 सालों में जो बनाया था वो केवल मंदिर नहीं था, वो विज्ञान का सार था तो कला का भंडार था। यह कलाकृति एक शिव मंदिर है जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है।

डॉ. नीलम महेंद्र

भारत ने एक बार फिर विश्व को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं किया बल्कि अपनी संस्कृति और कला का लोहा भी मनवाया। तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाना एक तरफ भारत के लिए गौरव का पल था तो विश्व के वैज्ञानिकों के लिए एक अचंभा भी था। दरअसल आज से लगभग 800 साल पहले निर्मित रामप्पा मंदिर सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है बल्कि ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण भारत के गौरवशाली अतीत का जीवित प्रमाण भी है। यह पत्थरों पर उकेरा हुआ एक महाकाव्य है। वो महाकाव्य जो 800 सालों से लगातार शान से भारत की वास्तुकला और विज्ञान की गाथा गा रहा है। और अब तो इसके सुर विश्व के कोने-कोने को मुग्ध कर रहे है। रामप्पा मंदिर का एक मंदिर से विश्व धरोहर बनने का यह सफर लगभग 800 साल लंबा है जो शुरू हुआ था 1213 में जब तेलंगाना के तत्कालीन काकतीय वंश के राजा गणपति देव के मन में एक ऐसा शिव मंदिर बनाने की प्रेरणा जागी जो सालों साल उनकी भक्ति का प्रतीक बनकर मजबूती के साथ खड़ा रहे। यह जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी वास्तुकार रामप्पा को। और रामप्पा ने भी अपने राजा को निराश नहीं किया। उन्होंने अपने राजा की इच्छा को ऐसे साकार किया कि राजा को ही मोहित कर लिया। इतना मोहित कि उन्होंने मंदिर का नामकरण रामप्पा के ही नाम से कर दिया। आखिर राजा मोहित होते भी क्यों नहीं, रामप्पा ने राजा के भावों को बेजान पत्थरों पर उकेर कर उन्हें 40 सालों की मेहनत से उसे एक सुमधुर गीत जो बना दिया था। जी हां, रामप्पा ने 40 सालों में जो बनाया था वो केवल मंदिर नहीं था, वो विज्ञान का सार था तो कला का भंडार था। यह कलाकृति एक शिव मंदिर है जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसी शिल्पकार के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसके द्वारा बनाया गया मंदिर उसके नाम से जाना जाए। आज भी यह विश्व का शायद इकलौता मंदिर है जो अपने वास्तुकार के नाम पर जाना जाता है। मशहूर खोजकर्ता मार्को पोलो ने जब इसे देखा था तो इसे 'मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला सितारा' कहा था।

आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में? दअरसल जब इस मंदिर का अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों और पुरातत्वेत्ताओं के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि इसका कला पक्ष भारी है या इसका तकनीकी पक्ष।

सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यह चमत्कार है या विज्ञान कि 17 वीं सदी में जब इस इलाके में 7.7 से 8.2 रेक्टर स्केल का भीषण भूकंप आया था जिसके कारण इस मंदिर के आसपास की लगभग सभी इमारतें ध्वस्त हो गई थीं, लेकिन 800 साल पुराना यह मंदिर ज्यों का त्यों बिना नुकसान के कैसे खड़ा रहा? इस रहस्य को जानने के लिए मंदिर से एक पत्थर के टुकड़े को काट कर जब उसकी जांच की गई तो पत्थर की यह विशेषता सामने आई कि वो पानी में तैरता है। राम सेतु के अलावा पूरे विश्व में आजतक कहीं ऐसे पत्थर नहीं पाए गए हैं जो पानी में तैरते हों। यह अभी भी रहस्य है कि ये पत्थर कहां से आए क्या रामप्पा ने स्वयं इन्हें बनाया था? आज से 800 साल पहले रामप्पा के पास वो कौन सी तकनीक थी जो हमारे लिए 21 वीं सदी में भी अजूबा है?

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को उसका यह स्वरूप देने से पहले रामप्पा ने ऐसा ही एक छोटा सा मंदिर बनाया था जिसे हम आज के दौर में प्रेजेंटेशन मॉडल कहते हैं। इसके बाद ही रामप्पा ने इस रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया।

छः फुट ऊंचे सितारे के आकार के प्लेटफार्म पर बनाए गए 1000 पिलर वाले इस मंदिर की नींव सैंडस्टोन तकनीक से भरी गई थी जो भूकम्प के दौरान धरती के कम्पन की तीव्रता को कम करके इसकी रक्षा करती है। इसके अलावा मंदिर की मूर्तियों और छत के अंदर बेसाल्ट पत्थर प्रयोग किए गए हैं। अब यह वाकई में आश्चर्यजनक है कि वो पत्थर जिसे डायमंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही काटा जा सकता है वो भी केवल एक इंच प्रति घण्टे के दर से। कल्पना कीजिए आज से 800 से साल पहले भारत के पास केवल ऐसी तकनीक ही नहीं थी बल्कि कला भी बेजोड़ थी। इस मंदिर की छत पर ही नहीं बल्कि पिलरों पर भी इतनी बारीक कारीगरी की गई है कि जो आज के समय में भी मुश्किल प्रतीत हो रही है क्योंकि उन पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियों की कटाई और चमक देखते ही बनती है। कला की बारीकी की इससे बेहतर और क्या मिसाल हो सकती है कि मूर्ति पर उसके द्वारा पहने गए आभूषण की छाया तक उकेरी गई है। आज 800 सालों बाद भी इन मूर्तियों की चमक सुरक्षित है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पत्थरों की यह मूर्तियां थ्री डी हैं। शिव जी के इस मंदिर में जो नन्दी की मूर्ति है खड़ी मूर्ति है जो इस प्रकार से बनाई गई है कि ऐसा लगता है कि नन्दी बस चलने ही वाला है। इतना ही नहीं इस मूर्ति में नन्दी की आंखें ऐसी हैं कि आप किसी भी दिशा से उसे देखें आपको लगेगा कि वो आपको ही देख रहा है। मंदिर की छत पर शिवजी की कहानियां उकेरी गई हैं तो दीवारों पर रामायण और महाभारत की। मंदिर में मौजूद शिवलिंग के तो कहने ही क्या! वो अंधेरे में भी चमकता है। आज एक बार फिर भारत की सनातन संस्कृति की चमक विश्वभर में फैल रही है।

(लेखिका वरिष्ठ स्तंभकार हैं।)

श्रीप्रकाश शर्मा

आप भी बन सकते हैं एक सफल रेडियो जॉकी

ब्रिटिश शासन काल में 8 जून 1936 को भारत में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गयी थी तो कदाचित किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि एंटरटेनमेंट और इनफार्मेशन का यह माध्यम एक दिन जनमानस के दिलों में इतनी गहराई से रच-बस जाएगा। रेडियो स्विच ऑन करने के साथ नृत्य-संगीत, ज्ञान-विज्ञान, सिनेमा और मनोरंजन के साथ खुशियों की जो इन्द्रधनुषी आभा खिल उठती है, वह तकनीक और विज्ञान की दुनिया से दूर रेडियो जॉकी का चमत्कार होता है। सच पूछिए तो एक रेडियो जॉकी रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने खड़ा वह जादूगर होता है जो मजेदार, चुट्कीले और जादुई बातों और प्रेरक प्रसंगों से श्रोताओं के दिल में खुशियों की बहार ले आते हैं।

रेडियो जॉकी कौन होता है?

सामान्य रूप से एक रेडियो जॉकी वह शख्स होता है जो किसी निश्चित टाइम पीरियड के लिए रेडियो पर शो की एंकरिंग या मेजबानी करता है। रेडियो जॉकी को प्रत्येक दिन या वीकेंड में अमूमन 3-4 घंटे का टाइम पीरियड श्रोताओं को एंटरटेन करने के लिए दिया जाता है। ये शोज टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाले टॉक शो और इंटरव्यू जैसे प्रोग्राम्स की तरह ही होते हैं जिसमें रेडियो जॉकी को भी एक निश्चित थीम दिया जाता है जिसके बारे में वे आमंत्रित गेस्ट से बात करते हैं, श्रोताओं से भी बातें करते हैं और उनके पर्सनल प्रोब्लम्स और प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कहानियां सुनाते हैं, न्यूज बुलेटिन पढ़ते हैं, श्रोताओं के फरमाइश पर गाने सुनाते हैं, श्रोताओं को खुश करने के लिए मिमिक्री करते हैं। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम के दौरान रिकार्डेड गाने बजाते हैं और म्यूजिक प्ले करते हैं और रेडियो पर विज्ञापनों को मैनेज करते हैं।

रेडियो जॉकी के लिए आवश्यक स्किल्स

रेडियो जॉकी का प्रोफेशन आसान नहीं होता है। अपनी बातों से श्रोताओं के दिल को गुदगुदा कर उनके लबों पर हंसी लाने की कला आसान नहीं होती है। कठिन मेहनत और निरंतर अभ्यास इस प्रोफेशन में सफलता की महत्वपूर्ण कसौटी मानी जाती है।

- दोषरहित और मधुर आवाज।
- वोईस मॉड्यूलेशन में प्रवीणता (भाव एवं दृश्य के अनुसार अपनी आवाज के पिच को एडजस्ट करने की कला)।
- शुद्ध डिक्शन और उच्चारण पर मास्टरी।
- देश-दुनिया के सभी डोमेन्स की गतिविधियों से पूरी तरह अपडेटेड रहना।
- भावों को सहज और स्वाभाविक रूप से बिना देर किये हुए अभिव्यक्त करने की क्षमता।
- विनोदी स्वभाव और प्रकृति।
- श्रोताओं को एंटरटेन करने के लिए क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग स्किल।
- अभिव्यक्ति की स्पष्टता, विशुद्ध उच्चारण।
- समाचार को रुचिकर ढंग से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने की कला।

रेडियो जॉकी का जॉब प्रोफाइल

- श्रोताओं को इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना और एनलाइटेन करना।
- विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से श्रोताओं को अपडेट करना।
- रेडियो के प्रोग्राम को होस्ट करना, एंकरिंग करना।
- विभिन्न गीत-संगीत कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना।
- म्यूजिक, फिल्म, डांस और फैशन के सेलिब्रिटीज और विभिन्न विधाओं और डोमेन्स में ख्यातिप्राप्त सख्शियतों का इंटरव्यू लेना।
- श्रोताओं के व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर देना, सलाह देना।

रेडियो जॉकी के रूप में करियर बनाने के लिए शुरुआत कहां से करें

रेडियो जॉकी के रूप में करियर की शुरुआत करने के लिए निम्नांकित दो रास्ते हैं:

यदि आप एक अच्छा वक्ता हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को अपडेटेड रखते हैं, लिखना आपकी आदत में शामिल है और स्वभाव से विनोदी प्रकृति के हैं तो ये मानिये कि आप रेडिओ जॉकी के लिए ही बने हैं। वैसे इस प्रोफेशन की शुरुआत किसी भी स्ट्रीम में बारहवीं परीक्षा पास करने के बाद की जा सकती है। मीडिया के बेसिक्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बारहवीं के बाद मास कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज या जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन करना आवश्यक होता है। इस कोर्स के दौरान अपने स्किल को निखारने और ग्राउंड लेवल पर एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए रेडियो स्टेशन में इंटर्न के रूप में कार्य करना जरूरी होता है।

रेडियो जॉकी के रूप में प्रोफेशन की शुरुआत करने का दूसरा रास्ता किसी भी डोमेन में ग्रेजुएशन के बाद रेडियो जॉकिंग या एंकरिंग या मास कम्युनिकेशन में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा से शुरू होता है।

इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो नियमित रूप से प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के लिए ऑडिशन कंडक्ट करती है। इन ऑडिशंस में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर वे ऑल इंडिया रेडियो में रिक्रूट किये जाते हैं। प्रसिद्द जॉकी के द्वारा कुछ ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स भी खोले गये हैं जो रेडियो जॉकिंग में कोर्स ऑफर करते हैं। अपनी वॉयस् को मॉड्यूलेट करने, शुद्ध डिक्शन और प्रननसियेशन को सीखने के लिए कुछ प्रोफेशनल क्रेश कोर्स और शोर्ट - टर्म वर्कशॉप्स भी हैं जो रेडियो जॉकी के लिए अनिवार्य स्किल को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं।

मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और रेडियो जॉकिंग कोर्स की स्टडी के लिए प्रमुख संस्थान

- रेडियो स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, मुंबई।
- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन।
- एपीजे इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली।
- सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पुणे।
- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, बंगलुरु।
- भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली।
- लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली।
- क्राफ्ट फिल्म स्कूल, नई दिल्ली।
- मद्रास क्रिस्चियन कॉलेज, चेन्नई।
- एशियन अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, मारवाह स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, नोएडा।

निजी क्षेत्र में एक रेडियो जॉकी के लिए रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है। रेडियो मिर्ची, बिग एफएम, रेड एफएम, रेडियो मिड-डे, रेडियो वाणी, टाइम्स एफएम इत्यादि प्राइवेट रेडियो कंपनियों में रेडियो जॉकी के लिए एम्प्लॉयमेंट अवसर बहुतायत में उपलब्ध हैं।

रेडियो जॉकी के लिए जॉब कहां उपलब्ध हैं

रेडियो जॉकी के रूप में प्रोफेशनल अवेन्यू और जॉब ओपोर्च्युनिटी का दायरा काफी विस्तृत है। रेडियो जॉकी के लिए आवाज उनका सबसे बड़ा एसेट होता है और यह उसके लिए जॉब पाने के चांस के साथ-साथ उसका अर्निंग पैकेज भी निर्धारित करता है।

वौइस् मोड्यूलेशन, क्लियर डिक्शन, फ्लाव्लेस प्रननसियेशन, देश-विदेश की गतिविधियों के अपडेट पर मास्टरी और लैंग्वेज और वकेब्यूलरी पर कमांड रेडियो जॉकी के लिए करियर और कंपनसेशन के पैरामीटर्स के रूप में कार्य करते हैं।

गवर्नमेंट सेक्टर

गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत एक रेडियो जॉकी ऑल इंडिया रेडियो के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के रेडियो स्टेशंस में भी विभिन्न पदों पर जॉब पा सकते हैं। इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट ओपोरच्युनिटीज की वेकेंसी की सूचना सरकार के द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

प्राइवेट सेक्टर

निजी क्षेत्र में एक रेडियो जॉकी के लिए रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है। रेडियो मिर्ची, बिग एफएम, रेड एफएम, रेडियो मिड-डे, रेडियो वाणी, टाइम्स एफएम इत्यादि प्राइवेट रेडियो कंपनियों में रेडियो जॉकी के लिए एम्प्लॉयमेंट अवसर बहुतायत में उपलब्ध हैं।

मीडिया और एंटरटेनमेंट

वर्तमान इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में रेडियो जॉकी के लिए मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी रोजगार के अनेकानेक अवसर खुल गये हैं। अल्टरनेटिव करियर के रूप में एक्सपीरियंस और फेम के साथ एक रेडियो जॉकी फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में एक्टर, प्रोडयूसर, स्क्रीनराइटर, डायरेक्टर के रूप में प्रवेश करके अपने करियर को बड़ी खूबसूरती से संवार सकते हैं।

एडवरटाइजिंग की दुनिया में भी रेडियो जॉकी कमर्शियल विज्ञापनों के लिए और फिल्मों, टेलीविजन और रेडियो पर वॉयस-ओवर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।

(लेखक प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, मामित, मिजोरम, हैं)

देसी गर्ल हिना

हिना खान फैंस के दिलों पर राज करती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हिना की एक झलक को आज फैंस बेकरार रहते हैं। हिना एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो साड़ी से लेकर बिकिनी तक में हुस्न का जल्वा बिखेरती रहती हैं। हिना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, और हाल ही में अपनी कुछ देसी अंदाज वाली फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन फोटोज में हिना प्रियंका चोपड़ा के देसी गर्ल वाले लुक में दिखाई दी हैं। फोटो में एक्ट्रेस सितारों वाली साड़ी पहने दिख रही हैं। एक्ट्रेस हर एक फोटो में अलग-अलग तरह से पोज मारती दिख रही हैं। गौरतलब है कि हिना की इस साड़ी को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। हिना खान ने अब बड़े पर्दे पर भी एंट्री की है। हिना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी फैंस के बीच छाई रहती हैं।

फाइटर सनी

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में सनी लियोन अपनी एक फिल्म के लिए एक्शन सीन करते हुए कैमरे के पीछे मस्ती करते हुए दिख रही हैं। इस वीडियो में सनी लियोन ने एक शख्स को मारने के लिए ट्राइपॉड उठा लेती हैं। इस बीच एक दूसरा शख्स बीच में आकर बचाव करता है। फिर सनी लियोन खुद को रोक लेती हैं। सनी लियोन के इस वीडियो को उनके कुछ फैंस भी देखकर हैरान हो गए हैं। सनी लियोन इस वीडियो में सच में कोई एक्शन करते हुए नहीं नजर आ रही हैं। बल्कि सनी लियोन शूटिंग के सेट पर अपनी फिल्म की टीम के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रही हैं।

इस वीडियो में एक शख्स तेजी से भागता हुआ खिड़की के भीतर घुसने की कोशिश करता है। इस पर सनी लियोन के पास में पड़ा कैमरा स्टैंड उठा कर उसे मारने जाती हैं तभी एक तीसरा शख्स आकर सनी को रोक लेता है। आपको बता दें कि सनी लियोन ने इन दिनों अपनी अपकमिंग तमिल फिल्म शेरो की शूटिंग में बिजी हैं। सनी लियोन अपने निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को लेकर इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं। शूटिंग के दौरान सनी लियोन कई बार मस्ती भरे वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

खुशियों की शुरुआत
और ज़िन्दगी भर का साथ
एलआईसी का
नया
जीवन
आनंद
UIN: 512N279V01
PLAN NO:815
LIC/06/16-17/78/HIN
परिपक्वता पर पूर्ण भुगतान और
उसके बाद आजीवन बीमा-सुरक्षा
का दोहरा लाभ लीजिए
• न्यूनतम मूल बीमा राशि : ₹1,00,000
• आयु योग्यता : 18-50 वर्ष
• अधिकतम परिपक्वता आयु : 75 वर्ष
• ऋण सुविधा उपलब्ध
• दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राईडर उपलब्ध
हमें फॉलो करें : YouTube LIC India Forever
अपने एजेन्ट/शाखा से सम्पर्क करें या हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर विज़िट करें
या SMS करें 'आपके शहर का नाम', 56767474 पर (जैसे कि 'MUMBAI')
नकली फ़ोन कॉल्स और जाली/धोखाधड़ी वाले ऑफर्स से सावधान रहें. आईआरडीएआई जनता को स्पष्ट करता है • आईआरडीएआई या इसके अधिकारी किसी प्रकार के इंश्योरेन्स या फायनान्शियल प्रोडक्ट्स की बिक्री जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं और न ही प्रीमियम का निवेश करते हैं • आईआरडीएआई द्वारा किसी बोनस की घोषणा नहीं की जाती है. अगर किसी को ऐसे कोई फ़ोन कॉल्स प्राप्त हों तो कृपया ऐसे फोन कॉल के नंबर के विवरण के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.
LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और
शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
IRDAI Regn No.:512
हर पल आपके साथ

अक्षरा का चुम्मा

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह एक साथ कई फिल्मों और वीडियोज में काम कर चुके हैं। इन दोनों की जोड़ी को दर्शक आज भी खूब पसंद करते हैं। ऐसे में खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का एक भोजपुरी गाना 'आग लगे ना राजा' का वीडियो यूट्यूब पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खेसारी और अक्षरा के बीच किसिंग सीन भी फिल्माया गया है, जिसे देखने के बाद दर्शक अक्षरा सिंह की हॉट अदाओं के दीवाने हो गए हैं। वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री काफी शानदार लग रही है।

अभिषेक को लगी चोट

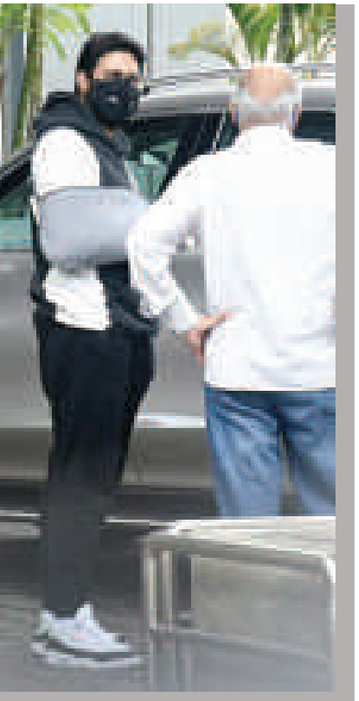

सदी के महानायक अमिताभ समेत पूरा बच्चन परिवार उस वक्त घबरा गया जब खबर मिली कि अभिषेक बच्चन को चोट लग गई है। अभिषेक को चोट कैसे, कब और कितनी लगी, इस बारे में तत्काल तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक को चोट लगने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमिताभ बच्चन, बेटी श्वेता के साथ अभिषेक से मिलने अस्पताल पहुंचे। सामने आई तस्वीरों में अमिताभ मुंह पर मास्क लगाए और हुडी पहने दिखे। बता दें कि हाल ही अभिषेक बच्चन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं, जिनमें उनकी दाहिनी बाजू में स्लिंग और कुछ बैंडेज बंधे हुए थे। जिस तरह बिग बी और श्वेता, उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और गंभीर दिख रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अभिषेक को ज्यादा चोट लगी है।

संकलन : **नीलाम कृष्ण**

We transform young minds into valued assets.

After a journey of 13 years,
we are the 20th best University in the country
as per NIRF Ranking 2020.

SIKSHA 'O' ANUSANDHAN
(DEEMED TO BE UNIVERSITY)
Re-accredited by NAAC with 'A' Grade

Khandagiri Square, Bhubaneswar-751030, Odisha, India

For admission please visit: www.soa.ac.in

SOA PRESS@16 July, 2020

RNI NO. DELHIN/2013/49824 Postal Reg. No. DL(E)-11/5427/2019-2021
Licenced to dispatch on Monday and Tuesday of every advance week at KNHO, Delhi-110051
Licenced to post pre-payment, Licence No. U(E)-08/2019-2021 Published for the week of SEPTEMBER 05-11, 2021

S-VYASA
Deemed to be University
Bengaluru, India

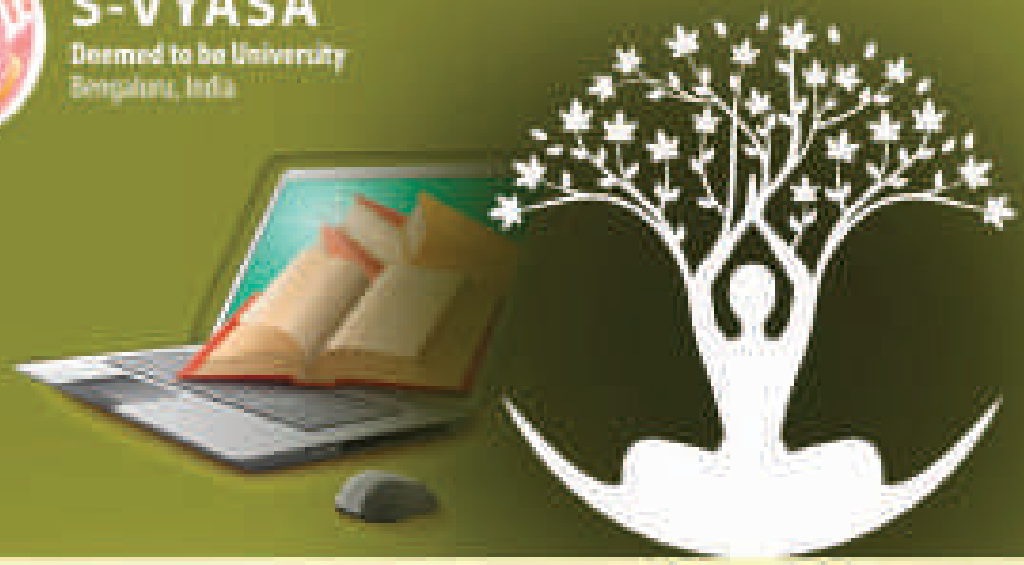

Short-term Online Courses

SNo	Course	Date & Time (IST)	Fee ₹
1	**Bharatanatyam - Intermediate Level** *by* Vid. Sri Pavan Kumar, Sri Krishna Kala Kunja®, Bengaluru	**21st July,** 15 sessions Mon - Fri, 6:00 - 8:30 pm	5000
2	**Yogic Counselling** *by* Dr. H R Nagendra, Chancellor, S-VYASA	**22nd July,** 10 sessions Mon - Fri, 9:00 - 10:00 am	4500
3	**Self-Management of Excessive Tension (SMET)**	**24th & 25th July,** 8 hrs Sat & Sun	4000
4	**Sanskrit Sandhi Rules and Patanjali Yoga Sutras** *by* Prof. Ramesh Chandra Panda, Dean - Division of Yoga Spirituality	**26th July,** 10 sessions Mon - Fri, 4:00 - 5:00 pm	3000
5	**Mind Sound Resonance Technique (MSRT):** (Batch - 2) *by* Ms. Gangotri Panda, S-VYASA	**28th July,** 10 sessions Mon - Fri, 11:00 am - 12:00 noon	2000

Yoga Instructor's Course (YIC)

12 Credit Course of 300 hrs of Learning
offered in **Residential** (1 month) & **Online Mode** (1 or 2 months)

Contact: **+91-80-2263 9901/ 02** ; Cell: **91-79759 27219**
E-mail: **onlineyogacourses@svyasa.edu.in** ; Apply Online @ **www.svyasa.edu.in**